

बांग्लादेश में सरकारी आदेश के जरिए शरिया कानून का ट्रायल

सरकारी दफ्तर में इस्लामी ड्रेस-कोड लागू

स्फी यायावर

बांग्लादेश में लोकतंत्र अब आखिरी सांस ले रहा है। देश में आम चुनाव कराने की बात तो दूर है, अब वहां शरिया शासन लागू करने की शुरुआत हो चुकी है। सरकारी संस्थाओं में शरिया कानून के तहत ड्रेस-कोड लागू किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश जारी किए जा रहे हैं। अब सरकार ने अध्यादेश जारी कर यह ताकीद

की है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस की किसी ने भी आलोचना की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, साथ

इस्लामी शासनतंत्रों आंदोलन (इस्लामी शासन की स्थापना का आंदोलन) के प्रमुख मुफ्ती सैयद मोहम्मद रजाउल करीम उर्फ मुफ्ती फौजुल करीम की

यूनुस की आलोचना करने वाले कर्मचारी बर्खास्त किए जाएंगे

ही उसे सख्त कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। चोमोनाई के प्रभावशाली पीर और अति-इस्लामी समूह

बांग्लादेश में शरिया-आधारित तालिबान शैली के शासन की मांग के बहाने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शरिया शासन



के तौर-तरीके अख्तियार करने शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश में

कट्टरपंथी एजेंडे के संस्थागत कार्यान्वयन के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। मुफ्ती की चौकाने वाली मांग और उस पर बांग्लादेश सरकार के

युनुस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तथाकथित प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और बुद्धिजीवी जमातें भी शातिराना चुप्पी साधे बैठी हैं।

कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं के लिए विशिष्ट इस्लामी ड्रेस कोड अनिवार्य करते हुए औपचारिक निर्देश जारी किया है। नए नियमों के अनुसार महिला कर्मचारियों को साड़ी या सलवार-कमीज पहनना होगा, अपने सिर को स्कार्फ या हिजाब से ढंकना होगा और छोटी बाजू या कम लंबाई के कपड़े, लेगिंग या किसी भी प्रकार के पश्चिमी

दो विवादास्पद आदेशों पर प्रगतिशील साथे हैं शातिराना चुप्पी

अंधानुकरण की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा होनी चाहिए थी, लेकिन निंदा के बजाय चुप्पी साध कर मोहम्मद

21 जुलाई को बांग्लादेश की शीर्ष संस्था केंद्रीय वित्तीय प्राधिकरण, बांग्लादेश बैंक के मानव संसाधन विभाग ने अपने

►10पर

मालदीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत

हमारे लिए दोस्ती हमेशा पहले आती है: मोदी

माले, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव की राजधानी माले पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइजु खुद मौजूद थे, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुइजु को गले लगा कर उनका स्वागत स्वीकार किया। हवाई अड्डे पर मालदीव के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ ही आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी पीएम मोदी की अगुवानी के लिए मौजूद थे। मालदीव के रिपब्लिकन स्कायर पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और मालदीव के राष्ट्रपति की धुनों के बीच पीएम मोदी का स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत



मालदीव और भारत की मजबूत दोस्ती पर लगाई मुहर

मालदीव को भारत देगा 4,850 करोड़ की ऋण सहायता

हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए खुद मौजूद थे मुइजु

दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए

ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

मालदीव की राजधानी में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे लिए दोस्ती हमेशा पहले आती है। सबसे पहले मैं भारत की जनता की ओर से मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति मुइजु और यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंधों की जड़ें समुद्र जितनी गहरी हैं। आज जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों में दोनों देशों की

►10पर



कानून मंत्री ने कहा, यह सरकार के विचार में ही नहीं

यह सवाल जानबूझ कर सदन में रखा गया ताकि इस पर तूल मचे और फिर यह मुद्दा संसद से सड़क तक जाए और संविधान का बोनसाई एडिशन पॉकेट से निकल कर ईवीएम तक नाचना शुरू कर दे। लेकिन इस सवाल को निर्मूल साबित करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, भारत सरकार ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को

►10पर

प्राचीन शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध

लगातार बढ़ रहा दोनों देशों का संघर्ष, अब तक 14 की मौत



बैंकॉक, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

11वीं सदी के ग्रीह विहार शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और शुक्रवार को भी दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी हुई। इस संघर्ष में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। संघर्ष के चलते एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। दोनों तरफ से हमले के लिए गोलीबारी, आर्टिलरी और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार को दोनों ही देशों की सेनाओं ने सीमा

पर सैनिकों के अतिरिक्त रेजीमेंट्स भेजे हैं। गुरुवार को कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड के सीमा पर स्थित गांवों पर हमला किया गया। इसके जवाब में थाईलैंड की सेना ने एफ-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमलों के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों से आम लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। साल 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तब सियाम और कंबोडिया के बीच सीमाएं तय की गई थीं। हालांकि, आगे चलकर 817 किमी लंबी इस सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। खासकर कुछ ऐतिहासिक मंदिरों, खासकर 11वीं सदी के ग्रीह विहार मंदिर को लेकर दोनों देशों में यह विवाद खासा गहरा गया।

►10पर

संसद के दोनों सदनों में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा

शत्रु की शैतानी और सेना की जांबाजी सुनेगा देश

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में होगी। सोमवार 28 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में भाग लेने वाले अन्य मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में भी 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। इसमें राजनाथ सिंह, जयशंकर और अन्य मंत्री भाग लेंगे। उच्च सदन में भी प्रधानमंत्री मोदी के चर्चा में हिस्सा लेने की उम्मीद है। दोनों सदनों में इस विषय पर 16 घंटे की चर्चा होगी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाएगा। न्यायपालिका में



संसद में आएगा भ्रष्ट जज को हटाने का प्रस्ताव

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दलों ने एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मांग

की थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष पहले दिन से ही संसद में हंगामा कर रहा है। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सदन को चलने नहीं दे रहा है। संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते में हम केवल एक विधेयक पारित कर पाए हैं। सभी विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही बाधित न करने का आग्रह करता हूं। रिजिजू ने कहा, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक बुलाई और यह दोहराया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आज यह निर्णय लिया गया है कि सोमवार 28 जुलाई को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण

►10पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड

सबसे लंबा खेलने वाले दूसरे पीएम बने मोदी

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4,078 दिन पूरे किए। इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक 4,077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रही थीं। प्रधानमंत्री के 26 मई 2014 से शुरू होकर 17 जून 2029 तक चलने वाले कार्यकाल को देखा जाए तो कुल

4,078 दिन पूरे मौजूदा कार्यकाल के 1423 दिन बाकी



5,501 दिन होते हैं। उसमें से प्रधानमंत्री ने 4,078 दिन पूरे किए, यानी इस कार्यकाल के मुताबिक 1423 दिन बाकी हैं। नरेंद्र मोदी 25 जुलाई यानी आज

लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

अभी तक लगातार सबसे लंबे समय तक (16 वर्ष 286 दिन) प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू के पास है। नरेंद्र मोदी 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए गैर-हिंदी राज्य के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री रही थीं। अगर

राज्य और केंद्र में सरकार का नेतृत्व करने की बात करें तो नरेंद्र मोदी का सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक रिकॉर्ड है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वह सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। वह पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कम से कम अपना

►10पर

6 साल में 16 करोड़ को मिला रोजगार

संसद में रखी गई पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट



नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

पिछले 6 साल में देश में बेरोजगारी घटी है। 2017-18 में कार्यरत लोगों की संख्या 47.5 करोड़ थी जो अब बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य

मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में भारतीय रिजर्व बैंक के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के आधार पर यह दावा किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि का भी जिक्र किया। पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए वर्कर पापुलेशन रेशियो 2019-20 में 28.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय ने पीएलएफएस के बारे में कहा कि यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लेबर फोर्स भागीदारी रेट 49.8 प्रतिशत (2017-18) से बढ़कर 60.1 प्रतिशत

►10पर

कहा कि जैन समाज की सरकारी पदों पर नियुक्तियों की महत्वाकांक्षा का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में जीतो केकेजी जोन सीएफडी संयोजक नितिन कठारिया, जीतो जैन बंधु योजना समिति सदस्य अमित कोठारी एवं समाज सेवी ताराचंद गुगलिया उपस्थित थे। भेंट के दौरान कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के निर्देशक मोहम्मद सिराज तथा कर्नाटक अल्पसंख्यक कांग्रेस के एडमिन इरशाद अहमद शेख विशेष रूप से मौजूद थे।

26वीं वाहिनी पीएसी के लिए 11 मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण

कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा उत्तर प्रदेश : योगी

गोरखपुर, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश आठ वर्ष पहले तक दंगा प्रदेश के रूप में बदनाम था, गुंडों-माफिया से तबाह था, वही उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा है। दंगामुक्त और गुंडामुक्त उत्तर प्रदेश आज अनुशासित और उत्सव प्रदेश की पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने 26वीं वाहिनी पीएसी परिसर में 11 मंजिला बैरक टावर तथा 30 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण किया।

सीएम योगी ने कहा कि आज कोई भी बाहरी व्यक्ति कानून व्यवस्था के मामले में यूपी पर हंस नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। यूपी का नौजवान आज कहीं भी जाता है तो सम्मान पाता है जबकि आठ वर्ष पहले यहां के नौजवान को यूपी के नाम पर एक कम्परा तक नहीं मिलता था। यूपी के नाम पर बाहर के लोगों के सामने डरावना दृश्य होता था। आज इन सबसे उबरकर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की नजीर प्रस्तुत करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना देश की बाह्य सुरक्षा का दायित्व संभालती है तो आंतरिक मामलों और कानून व्यवस्था के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत



महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर की पुलिस, लगातार पुलिसकर्मियों की कमी और अवस्थापना सुविधाओं की चुनौतियों से जूझ रही थी। आठ साल पहले यहां शांति की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, यह सपना था। तब पुलिस के लाखों पद खाली थे लेकिन नियत सही न होने से तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती थीं। कभी भर्ती में खामी तो कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट से रोक लग जाने के चलते नौजवान भटकने को मजबूर थे।

सीएम योगी ने अपनी सरकार के दौरान पारदर्शी पुलिस भर्ती प्रक्रिया की चर्चा करते हुए बताया कि आठ साल में 2 लाख 16 हजार भर्तियां यूपी पुलिस

में की गई हैं। इसमें न सिफारिश की गुंजाइश थी और न ही भ्रष्टाचार की। इन भर्तियों में हाल ही में हुई दुनिया की सबसे बड़ी 60244 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता थी। तब पुलिस के लाखों पद खाली थे लेकिन नियत सही न होने से तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती थीं। कभी भर्ती में खामी तो कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट से रोक लग जाने के चलते नौजवान भटकने को मजबूर थे।



को देखते हुए, प्रशासन ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो।

समय बीतने के साथ, इस जमीन के मालिक हक और कब्जे को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद गहराता चला गया। जिसके बाद मंदिर प्रबंध समिति और गुरुद्वारा प्रबंध समिति, दोनों ने ही उस जगह को लेकर अपना-अपना दावा किया।

यह विवाद लोकल कोर्ट में पहुंच गया, जहां यह मामला कई दशकों तक लंबित रहा। तीन हजार से साढ़े तीन हजार वर्गफीट भूमि को लेकर चल रहे इस विवाद में समय-समय पर अस्थायी निर्माण होते रहे, जिससे विवाद बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस दौरान धार्मिक भावनाएं भी गहराती रहीं, जिससे विवाद बढ़ता गया। लगभग दो महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह ने एक बार फिर दोनों पक्षों को सुलह के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार बातचीत भी हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रक्रिया और तेज हुई।

में की गई हैं। इसमें न सिफारिश की गुंजाइश थी और न ही भ्रष्टाचार की। इन भर्तियों में हाल ही में हुई दुनिया की सबसे बड़ी 60244 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता थी। तब पुलिस के लाखों पद खाली थे लेकिन नियत सही न होने से तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती थीं। कभी भर्ती में खामी तो कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट से रोक लग जाने के चलते नौजवान भटकने को मजबूर थे।



को देखते हुए, प्रशासन ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो।

समय बीतने के साथ, इस जमीन के मालिक हक और कब्जे को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद गहराता चला गया। जिसके बाद मंदिर प्रबंध समिति और गुरुद्वारा प्रबंध समिति, दोनों ने ही उस जगह को लेकर अपना-अपना दावा किया।

यह विवाद लोकल कोर्ट में पहुंच गया, जहां यह मामला कई दशकों तक लंबित रहा। तीन हजार से साढ़े तीन हजार वर्गफीट भूमि को लेकर चल रहे इस विवाद में समय-समय पर अस्थायी निर्माण होते रहे, जिससे विवाद बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस दौरान धार्मिक भावनाएं भी गहराती रहीं, जिससे विवाद बढ़ता गया। लगभग दो महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह ने एक बार फिर दोनों पक्षों को सुलह के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार बातचीत भी हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रक्रिया और तेज हुई।

में की गई हैं। इसमें न सिफारिश की गुंजाइश थी और न ही भ्रष्टाचार की। इन भर्तियों में हाल ही में हुई दुनिया की सबसे बड़ी 60244 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता थी। तब पुलिस के लाखों पद खाली थे लेकिन नियत सही न होने से तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती थीं। कभी भर्ती में खामी तो कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट से रोक लग जाने के चलते नौजवान भटकने को मजबूर थे।



को देखते हुए, प्रशासन ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो।

समय बीतने के साथ, इस जमीन के मालिक हक और कब्जे को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद गहराता चला गया। जिसके बाद मंदिर प्रबंध समिति और गुरुद्वारा प्रबंध समिति, दोनों ने ही उस जगह को लेकर अपना-अपना दावा किया।

यह विवाद लोकल कोर्ट में पहुंच गया, जहां यह मामला कई दशकों तक लंबित रहा। तीन हजार से साढ़े तीन हजार वर्गफीट भूमि को लेकर चल रहे इस विवाद में समय-समय पर अस्थायी निर्माण होते रहे, जिससे विवाद बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस दौरान धार्मिक भावनाएं भी गहराती रहीं, जिससे विवाद बढ़ता गया। लगभग दो महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह ने एक बार फिर दोनों पक्षों को सुलह के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार बातचीत भी हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रक्रिया और तेज हुई।

में की गई हैं। इसमें न सिफारिश की गुंजाइश थी और न ही भ्रष्टाचार की। इन भर्तियों में हाल ही में हुई दुनिया की सबसे बड़ी 60244 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता थी। तब पुलिस के लाखों पद खाली थे लेकिन नियत सही न होने से तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती थीं। कभी भर्ती में खामी तो कभी बेईमानी, भ्रष्टाचार के चलते कोर्ट से रोक लग जाने के चलते नौजवान भटकने को मजबूर थे।



को देखते हुए, प्रशासन ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो।

समय बीतने के साथ, इस जमीन के मालिक हक और कब्जे को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद गहराता चला गया। जिसके बाद मंदिर प्रबंध समिति और गुरुद्वारा प्रबंध समिति, दोनों ने ही उस जगह को लेकर अपना-अपना दावा किया।

यह विवाद लोकल कोर्ट में पहुंच गया, जहां यह मामला कई दशकों तक लंबित रहा। तीन हजार से साढ़े तीन हजार वर्गफीट भूमि को लेकर चल रहे इस विवाद में समय-समय पर अस्थायी निर्माण होते रहे, जिससे विवाद बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस दौरान धार्मिक भावनाएं भी गहराती रहीं, जिससे विवाद बढ़ता गया। लगभग दो महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह ने एक बार फिर दोनों पक्षों को सुलह के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार बातचीत भी हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रक्रिया और तेज हुई।



पुलिस लाइंस और पीएसी की वाहिनियों में अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। आज इस बात की प्रसन्नता है कि यूपी के हर थाने, पुलिस लाइंस और पीएसी की वाहिनियों में अवस्थापना सुविधाओं का जबरदस्त विस्तार हुआ है। कई जिलों में तो जो सबसे ऊंची मिनारनुमा बिल्डिंग होगी वह यूपी पुलिस के बैरक के रूप में होगी। सरकार एक तरफ अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ पूरी पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया को सम्पन्न कर रही है।

इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि पुलिस बल का लगातार मनोबल बढ़ाने और हर संसाधन देने के चलते योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए देश ही नहीं विदेश में भी जानी जाती है। यूपी पुलिस में इतनी

भर्तियां कभी नहीं हुईं जितनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई हैं। सीएम योगी की ताकतवर सोच से ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। पीएसी के एडीजी डॉ. रामकृष्ण स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए लोकार्पण की दोनों परियोजनाओं, बैरक टावर और हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य वाहिनियों में भी बहुमंजिला बैरक बनाया जा रहा है। यूपी में पहली बार महिला बटालियन का गठन और बटालियन भवन निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत गोरखपुर, लखनऊ और बदायूं में निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस में भर्तियों का नया रिकॉर्ड कायम किया है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है।

अखिल भारतीय संत समिति की घोषणा

प्रभावशाली 1000 हिंदुओं की तैयार होगी सूची

वाराणसी, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

दुनिया के प्रभावशाली 1000 हिंदुओं की सूची तैयार करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति ने अध्ययन शुरू कराया है। इसकी शुरुआत सतयुग से होगी। सनातन के वैभव को दुनिया को बताने के लिए हिंदू समाज के प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार की जा रही है। पहली सूची में सनातन धर्म के एक हजार प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है। प्राचीन काल से वर्तमान तक के सभी प्रभावशाली सनातनी हिंदू इस सूची में होंगे। अखिल भारतीय संत समिति अक्टूबर 2025 में होने वाली संस्कृति संसद में इस सूची को सार्वजनिक करेगी।

अखिल भारतीय संत समिति ने इसके लिए देश भर में शोध आरंभ कर दिया है। पहले चरण में 500 मृत और 500 जीवित हिंदुओं को शामिल किया गया है। संत समिति को हर साल इसे वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा। इसमें देश ही नहीं विदेश में रहने वाले हिंदू समाज के प्रभावशाली लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सूची में हिंदू वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, लेखक के साथ ही समाज पर विशेष प्रभाव डालने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। इस सूची में महाभारत के रचयिता वेदव्यास, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, योग सूत्र के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिलमुनि, न्यास दर्शन के गौतम, एटामिक थ्योरी के दार्शनिक कन्नडा, मीमांसा के जैमिनी, आदि शंकराचार्य, तमिल दार्शनिक थिरुवल्लीअर, पाणिनी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, चरक, सुश्रूत आदि का नाम शामिल किया गया है।

साथ ही गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर और गंगा विज्ञानी प्रो. जीडी अग्रवाल का भी नाम शामिल है। सूची पर अंतिम मुहर सितंबर माह में लगेगी। सूची में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रबींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रफुल्ल चंद्र रे, जगदीश चंद्र बोस, श्रीनिवास रामानुज, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाद साहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉ. बीआर अंबेडकर के नाम प्रमुख हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू समाज के गौरवशाली इतिहास और सामर्थ्य को विश्व स्तर पर बताने के लिए यह सूची तैयार कराई जा रही है। हिंदू समाज का देश ही नहीं दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान है। इस सूची के जरिए हम अपने योगदान को पूरे विश्व को बताएंगे कि हमने दुनिया को क्या दिया है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, योग सूत्र के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिलमुनि, न्यास दर्शन के गौतम, एटामिक थ्योरी के दार्शनिक कन्नडा, मीमांसा के जैमिनी, आदि शंकराचार्य, तमिल दार्शनिक थिरुवल्लीअर, पाणिनी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, चरक, सुश्रूत आदि का नाम शामिल किया गया है।

42 साल बाद एक साथ खुले मंदिर और गुरुद्वारा के द्वार

वाराणसी, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

वाराणसी के जगतगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल पिछले 42 वर्षों से बंद पड़ा था, उसे अब दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यह स्थल एक तरफ सिखों के पवित्र गुरुद्वारे और दूसरी ओर हिंदू समुदाय बड़े हनुमान मंदिर के रूप में श्रद्धा का केंद्र रहा है। 1984 के दंगों के दौरान इस जगह को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह की मध्यस्थता और दोनों पक्षों की सहमति के बाद अब इसे फिर से खोल दिया गया है। 21 जुलाई को परिसर के दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले हटने के बाद सिख और हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है।

इस जगह का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दोनों समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार, सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर करीब दो सौ साल पहले जब काशी आए थे, तब वे नीचीबाग क्षेत्र (जहाँ वर्तमान में गुरुद्वारा है) में रुके थे। वे अपने अनुयायियों से मिलने के लिए कई बार जगतगंज भी आए थे। इसलिए यह भूमि सिख समुदाय के लिए पूजनीय मानी जाती है। समय के साथ यहां एक गुरुद्वारा भी स्थापित हुआ। वहीं हिंदू समुदाय द्वारा यहां श्री बड़े हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। दोनों धार्मिक स्थल कई सालों से अस्तित्व में रहे और लोगों की आस्था का केंद्र बने रहे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख आंतरिक्षकों द्वारा हत्या के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। जगतगंज में स्थित यह स्थल गुरुद्वारा और मंदिर दोनों के लिए एक स्थान था। इसलिए प्रशासन ने किसी भी सांप्रदायिक तनाव या टकराव को रोकने के उद्देश्य से इस स्थल को सील कर दिया। उस समय मंदिर और गुरुद्वारा दोनों का पूरा तरह से निर्माण नहीं हुआ था। जिले में बढ़ते तनाव



को देखते हुए, प्रशासन ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो।

समय बीतने के साथ, इस जमीन के मालिक हक और कब्जे को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद गहराता चला गया। जिसके बाद मंदिर प्रबंध समिति और गुरुद्वारा प्रबंध समिति, दोनों ने ही उस जगह को लेकर अपना-अपना दावा किया।

यह विवाद लोकल कोर्ट में पहुंच गया, जहां यह मामला कई दशकों तक लंबित रहा। तीन हजार से साढ़े तीन हजार वर्गफीट भूमि को लेकर चल रहे इस विवाद में समय-समय पर अस्थायी निर्माण होते रहे, जिससे विवाद बढ़ता गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस दौरान धार्मिक भावनाएं भी गहराती रहीं, जिससे विवाद बढ़ता गया। लगभग दो महीने पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नारायण सिंह ने एक बार फिर दोनों पक्षों को सुलह के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार बातचीत भी हुई।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रक्रिया और तेज हुई।

धर्मांतरण के ग्लोबल नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक लड़ाई

जलालुद्दीन छांगुर हो या आगरा के जेहादी, सबका होगा हिसाब

लखनऊ, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश में हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे सुनियोजित धर्मांतरण के नेटवर्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कड़ा प्रहार शुरू हो गया है। हाल के दिनों में बलरामपुर, आगरा और प्रयागराज जैसे विभिन्न जिलों में सामने आई घटनाएं यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि यह केवल छिटपुट आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि एक गहरी, सुनियोजित और अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जो भारत की सनातन संस्कृति और सामाजिक संरचना को भीतर से तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। योगी सरकार इसे साफ्ट टेयर मानते हुए अब निर्णायक कार्रवाई की दिशा में बढ़ चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट चेतावनी सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा को चरितार्थ करते हुए राज्य पुलिस ने हाल के दिनों में बड़े धर्मांतरण गिरोहों का पर्दाफाश किया है। आगरा से लापता दो बहनों के रहस्यमयी मामले की जांच करते हुए पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसकी जड़ें छह राज्यों तक फैली थीं। तो बलरामपुर में जलाल-उद्दीन छांगुर के बहुराष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह की कहानियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बलरामपुर की घटना में उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ता ने धर्मांतरण गिरोह और अवैध वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरिन की हिरासत ले ली है। एटीएस अवैध वित्तपोषण से खरीदी गई बेनामी सम्पत्तियों का भी पता लगाएगी। एटीएस

ने 5 जुलाई को जलालुद्दीन और नसरिन को बलरामपुर में माधपुर गांव से गिरफ्तार किया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू उर्फ नसरिन पर वित्तीय प्रोत्साहन, शादी के प्रस्ताव और दबाव बनाकर कर्मजोर तबके के लोगों को इस्लाम कबूल कराने का आरोप है। जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। दो अन्य आरोपियों, नवीन उर्फ जलालुद्दीन और महबूब (जलालुद्दीन के बेटे) को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में ये लखनऊ की जेल में बंद हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सहयोगियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लगभग एक एकड़ क्षेत्र में फैले छांगुर और उसके सहयोगी नीतू की सम्पत्तियों पर प्रशासन ने नोटिस चर्षा किया था जिसमें अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया था। छांगुर की कोठी करीब एक एकड़ भूभाग में बनी थी जिसमें 2 बिस्वा जमीन सरकारी थी जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। इसी मामले में एक आरोपी रऊफ के खिलाफ पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन ने रऊफ के घर को अवैध निर्माण मानते हुए बुलडोजर कार्रवाई में सुनिश्चित की है। यह सीएम योगी की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत संगठित अपराधों में शामिल लोगों की अवैध कमाई से अर्जित सम्पत्तियों को ध्वस्त कर उन्हें आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ा जा रहा है।

इसी तरह, आगरा के मामले में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह सुनियोजित तरीके से हिंदू

युवतियों को प्रेमजाल, प्रलोभन, भय, विवाह और बहकावे जैसे हथियारों के माध्यम से फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण कर रहा था। यही नहीं, इनके पास से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे साफ संकेत मिलता है कि इनका संबंध अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी हो सकता है। एक आरोपी के पास से फिलीस्तीन का नक्शा और अरबी में छपे कट्टर इस्लामी विचारधारा वाले पोस्टर बरामद हुए हैं। साथ ही ईसाई मिशनरी से जुड़ा साहित्य भी मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह नेटवर्क हिंदू विरोधी एजेंडे के साथ सक्रिय था। अब तक की जानकारी के मुताबिक यह गिरोह केवल एक दो शहरों तक सीमित नहीं था। इसके नेटवर्क का विस्तार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ था। आरोपी युवकों को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता था कि कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करना है। पुलिस की विवेचना में ऐसे दर्जनों ऐसे मामलों की पहचान हुई है, जिनमें लव जेहाद के माध्यम से लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण किया गया। इनमें से कई लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाकर इस्लाम कबूल कराया गया, कुछ को दुबई भेजने की तैयारी थी, और कुछ को गोद लिया गया बताकर ईसाई मिशनरियों के पास भेजा गया। इस गंभीर प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तत्परता, स्पष्टता और प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित कराई है, वह बताता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी हाल में धर्मांतरण उद्योग का अड्डा नहीं बनने देगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं किया जाएगा कि हमारी बहन-बेटियों को आस्था और पहचान को खत्म करने का दुरसाहस कोई करे। सनातन विरोधी इस

कुचक्र को जड़ से समाप्त किया जाएगा। प्रदेश पुलिस और विशेष टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से जो सघन कार्रवाई की है, वह सराहनीय ही नहीं, बल्कि मिसाल के रूप में पूरे देश के लिए प्रेरणा है। 18 टीमें गठित की गईं, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञों और साइबर सेल को भी जोड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच से गिरोह की सम्पूर्ण गतिविधियों का डिजिटल नक्शा खींचा गया। इस जांच से यह भी पता चला कि ये लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें बहला-फुसलाकर कट्टरपंथी संगठनों के जाल में फंसाते थे। आगरा, मेरठ, हापुड, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, और गाजियाबाद जैसे शहरों में यह नेटवर्क बहुत गहराई तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, कई मामलों में लड़कियों को पहचान बदलने, नया नाम और नया धर्म अपनाने के लिए मानसिक, सामाजिक और शारीरिक दबाव डाला गया। कुछ युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें धमकाया गया था कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा या उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में धर्मांतरण के विरुद्ध कड़ा कानून लागू किया गया था। उस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि जो लोग लव जेहाद जैसे षड्यंत्रों के जरिए समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब इस हालिया कार्रवाई से यह फिर सिद्ध हुआ है कि प्रदेश में कानून सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि हर हाल में लागू किया जा रहा है।

काशी विद्वत परिषद ने जारी की हिंदू आचार संहिता

दहेज प्रथा, शादियों की बेमानी भव्यता और धर्मांतरण पर लगाएगी अंकुश

वाराणसी, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

काशी विद्वत परिषद ने नई हिंदू आचार संहिता जारी की है, इसके जरिए दहेज प्रथा, भव्य शादियों और धर्मांतरण पर अंकुश लगाने की कवायद की जाएगी। काशी विद्वत परिषद ने हिंदू परंपराओं और सामाजिक व्यवहार में सुधार के लिए एक नई हिंदू आचार संहिता जारी की है। 400 पन्नों के इस दस्तावेज को देश भर के विद्वानों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और संतों के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। नई संहिता

में दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध, शादियों में फिजूलखर्ची पर रोक और दिन में वैदिक तरीके से विवाह करने की सलाह दी गई है। अंतिम संस्कार के बाद होने वाले भोज में केवल 13 लोगों को शामिल करने की सीमा तय की गई है। इसके साथ ही प्री-वेडिंग शूट और सगाई जैसी आधुनिक प्रथाओं को भी हतोत्साहित किया गया है। संहिता में हिंदू धर्म में वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिन लोगों ने किसी दबाव में धर्म परिवर्तन कर

लिया था, वे लोग अपने गोत्र और नाम सहित हिंदू धर्म में वापस लौट सकेंगे। इसके साथ ही मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों के गर्भगृह में केवल पुजारियों और संतों के प्रवेश की अनुमति होगी। काशी विद्वत परिषद के महासचिव राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि इस संहिता को 70 विद्वानों द्वारा विकसित किया गया है। ये विद्वान 11 टीमें और तीन उप-टीमों में विभाजित थे। प्रत्येक टीम में उत्तरी और दक्षिणी भारत के पांच विद्वान शामिल थे। संहिता को अंतिम रूप

देने के लिए 40 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने बताया कि इस संहिता की 5 लाख प्रतियां पूरे देश में बांटी जाएंगी।

इस संहिता को तैयार करने में मनुस्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति के साथ-साथ गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अंशों को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2025 में शंकराचार्यों, रामानुजाचार्यों और प्रमुख संतों की स्वीकृति के बाद इस संहिता को आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा।

संपादकीय

उपराष्ट्रपति का इस्तीफा

उपराष्ट्रपति

जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पद से अचानक ही इस्तीफा देकर देश को चौंका दिया। वह देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे और अभी 10 अगस्त, 2027 तक उनका कार्यकाल शेष था। बीते दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यदि ईश्वर की कृपा रही, तो अगस्त, 2027 में सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। वह देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 67-ए के मुताबिक इस्तीफे को ‘तत्काल प्रभावी’ मानने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेषित इस्तीफे में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट का आभार जताया है। प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन को ‘अमूल्य’ माना है। सांसदों के स्नेह और सम्मान को धन्यवाद दिया है। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे में भारत की प्रगति, आर्थिक विकास और परिवर्तनकारी युग का साक्षी बनने, बल्कि उसका भागीदार होने की भावुक बात कही है। आज जब वह यह पद छोड़ रहे हैं, तो उनके दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। स्वतंत्र भारत के गणतांत्रिक इतिहास में वीवी गिरि ने 20 जुलाई, 1969 को और आर. वेंकटरमन ने जुलाई, 1987 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे दिए थे। गिरि राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते थे और

वेंकटरमन राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके थे। बहरहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस फैसले की पृष्ठभूमि में सेहत और बीमारी की बड़ी वजह हो सकती है। वैसे इस पद पर आसीन लोगों की बीमारियां काफ़ूर हो जाती हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की निरंतर निगरानी रहती है। संभव है कि अब धनखड़ के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता हो और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी हो, लेकिन उनकी तबीयत इतनी नाजुक भी नहीं है कि वह उपराष्ट्रपति पद का दायित्व निभाने में असमर्थ और अक्षम महसूस कर रहे हों! यह सतही तौर का कारण हो सकता है। अलबत्ता यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जो पत्रकार और नेता उनके संसदीय कार्यकाल के दौरान संकटग्रिस्त रहे हैं उन्हें करीब से जानने के मौके मिले हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि उपराष्ट्रपति बीते कुछ अंतराल से परेशान दिख रहे थे। उनका कहना है, तो उनके दिल में भारत की इस्तीफा यह भी सत्यापित करता है कि सरकार, सत्ता और ख़ास कर भाजपा के भीतर सब कुछ सहज नहीं है। सरकार के भीतर विरोधाभास और संकट हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ संघ-भाजपा पृष्ठभूमि के नेता नहीं थे। वह लोकदल और जनता दल की राजनीति से आए थे। चौधरी देवीलाल ने उन्हें राजनीति में उतारा था, नतीजतन 1989 में वह राजस्थान के झुंझुन क्षेत्र से चुन कर लोकसभा में पहुंचे। तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार में राज्यमंत्री भी रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में आए और 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो प्रधानमंत्री उनकी राजनीतिक सोच को अच्छी तरह जान चुके थे। फिर उन्हें 11 अगस्त, 2022 को देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो फोकस था कि एक बड़े किसान और जाट नेता के तौर पर उन्हें मान्यता दी जाए। बहरहाल हम सिर्फ सेहत को ही इस्तीफे का कारण मानने को तैयार नहीं हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, तो वह राज्यसभा के सभापति के आसन पर विराजमान थे। सदन की कार्यवाही संचालित करते रहे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के साथ मज़ाक करते रहे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। शाम को विपक्ष के सांसदों से भी मुलाकात की। बेशक बीते दिनों उनके सीने में दर्द उठा था और उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन चिकित्सकों के बुनियादी इलाज के बाद वह बाहर आ गए। मानसून सत्र की मुलाकातों के दौरान इतना-सा भी संकेत नहीं दिया कि वह इस्तीफा देने जा रहे हैं अथवा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, लिहाजा माना जा सकता है कि सरकार और उनके दरमियान ऐसे मतभेद उभर आए होंगे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठोस कारण की घोषणा वह स्वयं किसी किताब में करेंगे अथवा सरकार से छन कर सूचनाएं बाहर आएंगी। हम उन्हें जितना जानते हैं, उसके मद्देनजर दावा कर सकते हैं कि वह योद्धा किस्म के नेता रहे हैं। कोई भी किसी भी तरह के दबाव में उन्हें इस्तीफा देने को बाध्य नहीं कर सकता। बेशक वह अक्खड़, साफगो किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन बेहद कोमल, सीढ़ाढ़ और पार्टीबाज नेता भी रहे हैं। अब आगे अटकलें ही जारी रहेंगी। बाद में मिली सूचनाओं के अनुसार राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

कुछ अलग

शादी का नया उपन्यास

शादी

का एक नया उपन्यास और बहुप्रति प्रथा का विन्यास सिरमौर में हो रहा है। डा. वाईएस परमार के शोध में उस समय उफान आया जब सिरमौर के दो भाइयों प्रदीप व कपिल नेगो ने कुन्हाट गांव की एक बेटी सुनीता से शादी रचा ली। जाहिर है इस प्रथा और परंपरा की गवाही में सैकड़ों लोग जुटे और प्रचार की सीमा को लांघता यह विवाह बहस का मुद्दा बन गया। बहस प्रथा के बाहर, संविधान के साथ और आधुनिकता के बोध में यह है कि क्या स्त्री स्वाभिान, संस्कृति के परिचालन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता में आज भी उन्हीं मान्यताओं की बंधुआ है, जो उसे एक निश्चित सांचे में रखती हैं। पत्नी को संपत्ति मान लेना न्यायसम्मत नहीं हो सकता। न औरत आर्थिक मशीन है और न ही भूमि के रिकार्ड की शिला। आखिर ऐसी शायियां बचा किसे रहीं। जमीनी की हिस्सेदारी या परंपराओं के स्वनिर्धारित उसूलों को। बेशक तीन लोगों की सहमति से इस शादी की वैचारिकी को सामाजिक समर्थन मिल जाए या तारीफ यह हो कि दो भाई अपने समुदाय की ताजपोशी में एक सेहरा-एक पत्नी हो गए, लेकिन इस घटनाक्रम ने देश और प्रदेश की तस्वीर में एक चुनौती परोस दी है। कल अगर परंपरावादी समाज लोटर कर देगा के हर हिस्से में प्राचीन मान्यताओं को जिंदा रखेगा, फिर हर तर्क के तीरों से बंधे हम ही होंगे। मसलन जिन पौधियों में पढ़ कर दो पति एक पत्नी की कहानी में अमर होने लगे, वहां पत्नी का पुनः सती होना भी नागरिक समाज को अपना गौरव खोज लाएगा।

कुछ अलग

शादी का नया उपन्यास

शादी का एक नया उपन्यास और बहुप्रति प्रथा का विन्यास सिरमौर में हो रहा है। डा. वाईएस परमार के शोध में उस समय उफान आया जब सिरमौर के दो भाइयों प्रदीप व कपिल नेगो ने कुन्हाट गांव की एक बेटी सुनीता से शादी रचा ली। जाहिर है इस प्रथा और परंपरा की गवाही में सैकड़ों लोग जुटे और प्रचार की सीमा को लांघता यह विवाह बहस का मुद्दा बन गया। बहस प्रथा के बाहर, संविधान के साथ और आधुनिकता के बोध में यह है कि क्या स्त्री स्वाभिान, संस्कृति के परिचालन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता में आज भी उन्हीं मान्यताओं की बंधुआ है, जो उसे एक निश्चित सांचे में रखती हैं। पत्नी को संपत्ति मान लेना न्यायसम्मत नहीं हो सकता। न औरत आर्थिक मशीन है और न ही भूमि के रिकार्ड की शिला। आखिर ऐसी शायियां बचा किसे रहीं। जमीनी की हिस्सेदारी या परंपराओं के स्वनिर्धारित उसूलों को। बेशक तीन लोगों की सहमति से इस शादी की वैचारिकी को सामाजिक समर्थन मिल जाए या तारीफ यह हो कि दो भाई अपने समुदाय की ताजपोशी में एक सेहरा-एक पत्नी हो गए, लेकिन इस घटनाक्रम ने देश और प्रदेश की तस्वीर में एक चुनौती परोस दी है। कल अगर परंपरावादी समाज लोटर कर देगा के हर हिस्से में प्राचीन मान्यताओं को जिंदा रखेगा, फिर हर तर्क के तीरों से बंधे हम ही होंगे। मसलन जिन पौधियों में पढ़ कर दो पति एक पत्नी की कहानी में अमर होने लगे, वहां पत्नी का पुनः सती होना भी नागरिक समाज को अपना गौरव खोज लाएगा।

दृष्टि कोण

अतिवृष्टि की बाढ़ से घिरा जमजीवन

जब से ऋतुचक्र विगड़ है तब से वर्षा का वर्षण भी अनिश्चित हो चुका है। इसी वर्षा ऋतु से पहले चारों ओर अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ ने जनजीवन के लिए मृत्यु से लेकर अनेक तक अन्य संकट उत्पन्न कर दिए हैं। पंचांग तथा वार्षिक अंकपत्र के अनुसार श्रावण मास अब कुछ दिन पूर्व ही आरंभ हुआ है, किंतु अत्यधिक वर्षा के कारण देश के अधिसंख्य प्रांत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के कई प्रांतों में भी बाढ़ की स्थितियां-परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। मई के अंत से लेकर पूरे जून माह तक राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम में अनिश्चित, अनियंत्रित तथा उथल-पुथल मचाने वाली वर्षा ने जनजीवन को संकट में डाल दिया था। और अब जुलाई के पहले प्रंद्रह

ललित गर्ग

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों का फैसला और उठते सवाल

11 जुलाई 2006 को मुंबई की भीड़भरी लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया था। पीडित परिवारों के साथ-साथ जन-जन को आहत किया था। 17 जगहों पर हुए इन धमाकों में 187 निर्दोष लोगों की जान गई और 824 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। लेकिन इन बम धमाके को लेकर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने विशेष मकोका अदालत की ओर से 12 अभियुक्तों को दी गई सजा को गैरकानूनी करार दिया। इन सभी आरोपियों का बरी हो जाना सवाल के साथ-साथ चिन्ता भी पैदा करता है। इसीलिये करीब 19 साल बाद आए अदालत के इस फैसले को लेकर न केवल कानूनी दायरे में, बल्कि सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल वहीं घूमकर आ जाता है कि इतने बड़े नुकसान का दोषी कौन है? लम्बी न्यायिक प्रक्रिया एवं जांच के बाद 2015 में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 12 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला लगभग 8 वर्षों की सुनवाई, 250 से ज्यादा गवाहों और हजारों पन्नों की गवाही के बाद आया। लेकिन 2023 और फिर 2025 में कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों, मानवाधिकार समूहों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ दोषियों को पर्याप्त सबूतों के बिना फंसाया गया, पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण रही और कई जगह कानून के दायरे का अतिक्रमण किया गया। इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जिस तरह से एक-एक करके सारे सबूतों की ध्वजियां उड़ायीं, उससे पूरे सिस्टम को लेकर संदेह उठता है। जब इतने अहम मामले में इतनी लम्बर एवं लापरवाहीपूर्ण जांच हुई, तो फिर दूसरे तमाम केस में क्या होता होगा? गवाहों के बयान दर्ज करने से लेकर सबूत जुटाने तक, हर जगह लापरवाही एवं कौतूहली बरती गई। कानून की दृष्टि में अपराध केवल घटना नहीं, उस घटना के पीछे की मंशा, सबूतों की पुष्टि, प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी मूल्यांकन करता है। “दोषी को सजा मिलनी चाहिए।”-यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, लेकिन “निर्दोष को दंड न मिले”-यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है। भारतीय दंड संहिता, मकोका और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूपीए) जैसे सख्त कानून आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए, लेकिन इनका उपयोग अक्सर राजनीतिक प्रभाव, मीडिया ट्रायल, या जनभावनाओं को शांत करने के लिए किया गया है। ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में अनेक ज्वलंत सवाल खड़े हुए हैं कि क्या सभी दोषियों

ललित गर्ग

देश दुनिया से

राजस्व विभाग के दावे और किसान

एक

शायर की निम्न पंक्तियां राजस्व विभाग की भ्रष्ट व्यवस्था की दुखद अभिव्यक्ति हैं, और लगता है कि उसने भी जरूर व्यक्तिगत तौर पर इसके दश झेले होंगे। ‘जिस जमीन को समझते हो तुम अपनी मलकीयत तमियां, महकमा माल के हाकिमों और वकीलों का मुकद्दर है वो।’ हम मानते हैं कि जर, जेरू और जमीन ही हर विवाद की जड़ है। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस भी व्यक्ति का निजी जमीन से थोड़ा सा भी संबंध है, वह राजस्व विभाग और भ्रष्ट कर्मचारी लॉबी में भली प्रकार परिचित है। विभाग में अच्छे और ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी सुनता कौन है? मुी भर शातिर लॉबी सब पर भारी है। भू-माफिया, शातिर ग्रामीण और भ्रष्ट कर्मचारी लॉबी ने 90 फीसदी लोगों की नाक में दम कर रखा है। पुलिस और प्रशासन पर इनकी पूरी पकड़ है। ऊपर से राजनेताओं का इनके सिर पर वरदहस्त होता है। ये लोग कुछ भी करें, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्याय व्यवस्था की कलुआ चाल को देख कर उससे न्याय की अपेक्षा रखना बहुत बड़ी भूल है। दशकों से न्यायालयों में केस लंबित पड़े हैं। वकीलों के वारे-न्यारे हैं। भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं है। अन्याय का प्रतिकार कुर्बानी मांगता है जो सबसे वश की बात नहीं है। फिर वह इश्तामाल हो, बंदोबस्त हो या वर्तमान मुहाल की व्यवस्था, सबने मिलकर असमर्थ लोगों का कचमूर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीड़ित लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला और न ही निकट भविष्य में मिलने की कोई उम्मीद है। पता नहीं हमें क्या हो गया है। लगभग सभी का फोकस धन-दौलत बढ़ोतरी पर है। और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और यही हमारा दुर्भाग्य है। 1970 के दशक में हस्सीर (बड़सर) के एक गांव में इश्तामाल की प्रक्रिया शुरू हुई। सुरु और सुंदरी के दौर में चाम के दाम

ललित गर्ग

ललित गर्ग

अतिवृष्टि की बाढ़ से घिरा जमजीवन

धंधे, व्यवसाय, नौकरी, सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। अतिवृष्टि तथा बाढ़ के उपरांत निरंतर आकार लेने वाली जलजनित समस्याओं का निदान कुछ दिनों, सप्ताहों अथवा माहों में नहीं हो पाता। ऐसी समस्याएं वर्षौपर्यं बनी रहती हैं तथा समस्याग्रस्त लोगों के जीवन को अकल्पनीय बुराइयों के अधीन करके भयंकर ढंग से असुरक्षित कर देती हैं। भारत जैसे देश में जहां भूक्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर यूरोपीय देशों के बराबर अथवा उसने भी विशाल 28 राज्य व कई देशवासित प्रदेश विद्यमान हैं तथा पूरे विश्व में जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, वहां अतिवृष्टि हुए पानी तथा विशाल क्षेत्र में ठहरे हुए कीचड़-गाद-दंगरी से युक्त पानी के कारण अकल्पनीय समस्याएं होती हैं। प्रकार-प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रहन-सहन, भोजन, पेयजल, आजीविका, विद्यालय, शिक्षा, काम-

सम्पादकीय

ललित गर्ग

ललित गर्ग

सम्पादकीय

ललित गर्ग

को वास्तव में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर दोषी ठहराया गया है? यदि नहीं, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए एक गंभीर प्रश्न है। क्या पुलिस या जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच की? कई बार जांच एजेंसियों पर 'नतीजे पहले, जांच बाद में' का आरोप लगा है। क्या विशेष अदालतों का गठन निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है या त्वरित दंड की नीति अपनाता है? क्या कानून केवल सख्ती का पर्याय बन गया है या उसमें मानवीय संवेदना का स्थान है? क्या मीडिया ट्रायल ने वास्तविक न्याय को प्रभावित किया? इन प्रश्नों के उत्तर मिलना ही चाहिए। देश के सामने आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चुनौती है, तो वहीं न्याय की नैतिकता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। अगर कानून का इस्तेमाल अन्याय के लिए किया गया, तो आतंकवाद के खिलाफ जंग की नैतिकता ही सवालों में पड़ जाएगी। न्याय केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि नैतिक और विधिसम्मत संतुलन का नाम है। जो निर्दोष है, उसे दोषमुक्त करना और जो दोषी है, उसे यथोचित दंड देना- यही कानून का आदर्श उद्देश्य है। मुंबई बम धमाके जैसी वीथप्स घटनाएं देश के लिए चुनौती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के नाम पर अगर हम न्याय और कानून के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो हम एक असुरक्षित और अन्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगे। आवश्यक है कि न्याय केवल न्यायालयों की प्रक्रिया न रहे, वह जनविश्वास का प्रतीक बने। एक बड़ा सवाल है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे बना रहे? इसके लिये जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी हो, आरोपों की पुष्टि डिजिटल और वैज्ञानिक सबूतों से हो। अदालतें किसी दबाव, राजनीतिक प्रभाव या जनभावना से परे निर्णय लें। न्याय में देरी भी अन्याय है, लेकिन जल्दबाजी में न्याय भी गलत निर्णय की आशंका बढ़ाता है। सभी मामलों में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्र और निष्पक्ष पुरावावलोकन को सुनना रहे। निचली अदालतें हो या सर्वोच्च अदालतें-न्यायिक फैसलों का बदलना न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के लिये गंभीर चुनौती है। ऐसे अनेक मामले हैं

ललित गर्ग

ललित गर्ग

ललित गर्ग

किसान की पंद्रह-बीस दुरस्तियां बकाया हैं, उनकी दुरुस्ती के लिए उसकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। ललती एक पटवारी की और उसकी सजा व्यस्तताओं से घिरे किसान को ताउम्र भुगतनी पड़ती है। वाहरी व्यवस्था। किसान की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई होगी। दुरुस्ती की प्रक्रिया जटिल बन गई है। कालांतर में और पंजाबी ग़रदावर की प्रतिनियुक्ति हुई। रंजिश और ख़ुंदस के चलते वह दिवंगत ग़रदावर से भी आगे निकल गया क्योंकि शातिर लॉबी उसके समर्थन में खड़ी थी। इतने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। परिणति यह रही कि सीमा पर बुर्जियां संदिग्ध, रास्ते बस्तियों तक नहीं पहुंचे। वर्तमान सड़क किसी की मलकीयत है और जो कागजों में सड़क है, वहां किसी ने फसल बीजो से और पंजाबी ने निर्माण कर दिया है। लगता है कई पीढ़ियां कोर्ट में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगी। जहां तक बंदोबस्त का सवाल है, रही सही कसर उसने निकाल दी है। करमों से मीटर बनाते समय पांच से दस मीटर की कमीवैशी साधारण सी बात है। किसी के रकबे की चौड़ाई 11 करम से 16 मीटर की बजाय 20 मीटर कर दी गई और रकबा बढ़ जाने के डर से लंबाई की भुजाओं से 5 से 10 मीटर कम कर दिए गए। ऐसा अनर्थ, अनेक सप्तरस नंबरों में हुआ है। पंजाबी में तीन करम की चौड़ाई में बनी दुकानों को केवल चार मीटर दिए गए। पड़ोसी ने इसका लाभ उठा कर निशानदेही लेकर 22 मीटर लंबी जमीन पर कच्चा करे की तीन मंजिलें खड़ी कर दी। स्थानीय पंचायत ने कहा- निशानदेही लेकर निर्माण हुआ है, इसमें अतिक्रमण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाजारों और बस्तियों में करमों के हिसाब से बने बच्चा नहीं रहता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दशमलव में लिखे जाने चाहिए, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। हैरत की बात है कि एक अदद दुरुस्ती के लिए वर्षों का समय और हजारों रुपए वकीलों की फीस लगती है। जिस बेचारे

ललित गर्ग

ललित गर्ग

ललित गर्ग

होती है। इस लेखक ने उत्तराखंड के एक जनपद मुख्यालय से कुछ दूर स्थित एक लघु उपनगर में रहते हुए निरंतर दो वर्षों तक वर्षा की अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ में अपने आवास तथा उसके चहुँदो ओर के क्षेत्र को निरुपाय होकर केवल और केवल ईश्वर के भरोसे सुरक्षित होने की प्रार्थना करते देखा व भोगा है। ऐसी अतिवृष्टि, ऐसी बाढ़, ऐसी आपदा से प्रत्यक्ष प्रभावित लोग भाग्य के बूते ही जीवित रह पाते हैं। जिनका भाग्य निर्लक्ष होता है, वे असुरक्षित पर्यावास के उजड़ने-बहने के कारण मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। जीवित लोग भी केवल अपने शरीर के साथ जीवित होते हैं। उनका आवास, जीवनचर्या के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं, सभी कुछ आपदा में नष्ट हो जाता है। उनके लिए जीवन में प्रत्येक आवश्यकता, सुविधा तथा वस्तु को पुनः क्रय करके संग्रहीत करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

सम्पादकीय

ललित गर्ग

ललित गर्ग

सम्पादकीय

जिनमें निचली अदालतों में दिये गये मौत की सजा को ऊपरी अदालतों ने बदल दिया। जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज होते हुए बार-बार देखे गये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक आरोपी की मौत की सजा को खारिज करते हुए कहा कि ‘जब दांव पर इंसानी ज़िंदगी लगी हो और उसकी कीमत खून हो, तो मामले को पूरी ईमानदारी से देखा जाना चाहिए।’ दुर्भाग्य से मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की जांच में इस भावना का इशारा है पालन नहीं किया गया। इस मामले में सभी आरोपियों का बरी हो जाना न केवल न्याय प्रक्रिया पर बल्कि जांच एजेंसियों पर सवाल पैदा करता है। प्रश्न है कि अगर 12 लोग निर्दोष थे तो इतने बरसों तक आतंकी होने का दाग लिए जिल्लत की ज़िंदगी क्यों जीते रहे? अगर ये दोषी थे तो जांच इतनी कमजोर क्यों हुई? यह केस निचली अदालतों के कासकाज के तरीकों पर भी बड़ा सवालिया निशान है। सबूतों को लेकर इतने संदेह थे, लेकिन निचली अदालत ने उन पर गौर नहीं किया। यह पहला मामला पूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति है। यह पहला मामला नहीं, जहां जांच में खामियों, गवाही में कमी और कमजोर सबूतों के चलते ऊपर की अदालतों में केस खारिज हो गया हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते तीन लोगों की मौत की सजा रह करते हुए उन्हें हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने भी 2011 में हुई दोहरी हत्या और रेप के आरोपी को छोड़ने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने जांच में गंभीर कमियां गिनाई थीं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि झूठे मुकदमों की वजह से जिन्हें लंबा समय जेल में बिताना पड़ा है, उन्हें मुआवजा देने के लिए कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। अब मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन बम ध्माके में आरोपियों को निर्दोष छोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की है। देश उम्मीद करता है कि इस बार तथ्यों को सही ढंग से रखा जाएगा। यह केवल एक केस नहीं, न्याय व्यवस्था पर आम लोगों के चकौन का मामला है। भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस और अदालतें लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं, वर्षों लम्बी न्याय प्रक्रिया झेलने के बाद भी लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है, न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी आदर्श न्याय व्यवस्था में आम व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

आप का नजरिया

जाति जनगणना : भारत में सामाजिक न्याय की पुनर्परिभाषा

सामाजिक

न्याय की पुनर्परिभाषा
इंशा वारसी
एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो आज़ादी के बाद बंद हो चुकी एक बड़ी प्रथा की वापसी का प्रतीक है। समाज सुधारकों, विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा लंबे समय से मांगे जा रहे इस फैसले की देश में समानता को बढ़ावा मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में सराहना की जा रही है। ऐसे समय में जब समावेशी विकास राष्ट्रीय विमर्श का वेदं बिंदु है, जाति जनगणना आँकड़ों पर आधारित नीति निर्माण के एक ऐसे युग की शुरुआत का वादा करती है जो वास्तव में भारत के जटिल सामाजिक ताने-बाने को दर्शाता है। जाति जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना प्रव्रौरिया के एक भाग के रूप में किसी व्यक्ति की जातिगत पहचान पर आँकड़ों का व्यवस्थित संग्रह है।इसका उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण की सटीक और विस्तृत समझ हासिल करना है, जिससे सरकार सबसे वंचितों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियाँ बना सके। ऐतिहासिक रूप से, 1931 तक औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जाति संबंधी आँकड़े नियमित रूप से एकत्र किए जाते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, जाति गणना अनुसूचित जातियों (ए) और अनुसूचित जनजातियों (ए) के तहत ही सीमित थी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ॐ) और अन्य को व्यापक राष्ट्रीय आँकड़ों से बाहर रखा गया था। इस कमी को पूरा करने का अंतिम प्रयास, 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एण्ण), आंकड़ों की विसंगतियों और अविवशनीयता से प्रभावित रही, जिसका मुख्य कारण एक मानक जाति सूची का अभाव था। भारत ने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक दाये दिए हैं, लेकिन विश्वसनीय जाति आँकड़ों के बिना, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अक्सर अंधेरे में ही चलती हैं। वर्तमान में, ॐ के लिए आरक्षण नीतियाँ 1931 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं, जो धं की जनसंख्या को 52" बताती हैं। हालाँकि, राज्यस्तरी य सत्रेक्षण, जैसे कि बिहार का 2023 का जाति सत्रेक्षण, दर्शाता है कि ॐ और सबसे पिछड़े वर्ग राज्यों की जनसंख्या को 63" से अधिक हिस्सा हैं। इस तरह के निष्कर्ष कल्याणकारी लाभों और आरक्षणों के समान वितरण को सुनिाति करने के लिए एक अदृातन राष्ट्रीय जाति डेटाबेस की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने एसईसीसी 2011 की कमियों को दूर करने हेतु एक बेहतर गणना पद्धति की पुर्जोर वकालत की है, जहाँ खुली जाति रिपर्टिंग के परिणामस्वरूप 46 लाख से ज्यादा अलग-अलग प्रविष्टियाँ और 8 करोड़ से ज्यादा त्रुटियाँ हुईं। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य डेटा संग्रह की एक अधिक व्यवस्थित और सत्यापन योग्य प्ऱाि के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करना है। पहचान स्थापन के लिए आधार को जोड़ना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और छंटाई और वगाकरण के लिए एआई उपकरणों का लाभ उठाना इस प्राप्ति की विश्वसनीयता सुनिाति करने के प्रस्तावित उपायों में से हैं। केवल एक संख्य़ात्मक प्रव्रिया से कहीं अधिक, जाति जनगणना के सामाजिक समता और शासन पर गहरे प्रभाव हैं। विभिन्न समुदायों के वास्तविक जनसांख्यिकीय वितरण को उजागर करके, यह न्यायमरूति रोहिणी आयोग की सिफारिश के अनुसार, ओबीसी के भीतर पिछड़े समूहों के उप-वगाकरण की अनुमति देता है। यह सुनिाति करता है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचितों तक पहुँचे, न कि प्रमुख उपसमूहों द्वारा एकाधिकार कर लिया जाए। इसी प्रकार, सटीक जातिगत आँकड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पुनर्संतुलित करने और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ देकर लोकतंत्र को मज़बूत करने में मदद कर सकते हैं। इस कदम के महत्व को भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 340 राज्य को पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने का अधिकार देता है, और जाति जनगणना इसी अधिदेश के अनुरूप है। यह अनुच्छेद 15 और 16 के उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है, जो भेदभाव का निषेध करते हैं और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। हालाँकि, विश्वसनीय आँकड़ों के बिना, इस संवैधानिक विचारों के प्रतीकात्मक संकेतों में सिमट जाने का खतरा है। हालाँकि यह चिंता जताई गई है कि जातिगत जनगणनाएँ जातिगत पहचान को मज़बूत कर सकती हैं या राजनीतिक शोषण का साधन बन सकती हैं, ऐसे जोखिमों को पारदर्शा, नैतिक और न्यायसंगत कार्यान्वयन के माध्यम से कम किया जा सकता है। जातिगत जनगणनाओं को राजनीतिक के बजाय विकासात्मक साधन के रूप में उपयोग करना वे सामावेशी विकास के उद्देशर में बदल सकती हैं। निगरानी तंत्र, कानूनी सुरक्षा उपाय और नीति मूल्यांकन को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिाति हो सके कि आँकड़े केवल सामाजिक न्याय की सेवा करें, चुनावी अंकगणित की नहीं।





गाजा संघर्ष के बीच राष्ट्रपति मैक्रो की बड़ी घोषणा फिलिस्तीन को फ्रांस स्वतंत्र देश की मान्यता देगा

पेरिस, 25 जुलाई (एजेंसियां) । फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनका देश फिलिस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा। उन्होंने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वे इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय

सबसे जरूरी है कि गाजा में जारी युद्ध तत्काल खत्म हो और नागरिकों की जान बचाई जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के तहत मैंने फैसला लिया है कि फ्रांस, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। हमें हमारा को हथियार मुक्त कर गाजा को सुरक्षित बनाना और उसका पुनर्निर्माण करना होगा।

उन्होंने लिखा है कि तत्काल युद्धविराम, सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में व्यापक स्तर पर मानवीय मदद की जरूरत है। खास बात यह है कि मैक्रो इससे पहले इजराइल के रुख के समर्थक थे। 17 अक्टूबर 2023 को जब हमारा के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, तब राष्ट्रपति मैक्रो ने इजराइल का समर्थन किया। हालांकि हाल के महीनों में गाजा में इजराइल की व्यापक सैन्य कार्रवाई में आम लोगों के निशाना बनने और वहां खाद्यान्न

संकट को लेकर मैक्रो चिंतित हैं। एक दिन पहले भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में गाजा संकट पर बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि गाजा पट्टी में व्याप्त भीषण मानवीय संकट का समाधान केवल संघर्ष विराम में अस्थायी विराम से नहीं किया जा सकता। गाजा में लोग रोजाना भोजन, इंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

सीबीएस न्यूज़ पर होगा स्काईडॉस का नियंत्रण, पैरामाउंट का होगा विलय

वाशिंगटन। अमेरिका के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीबीएस न्यूज़ पर बहुत जल्द हॉलीवुड स्टूडियो



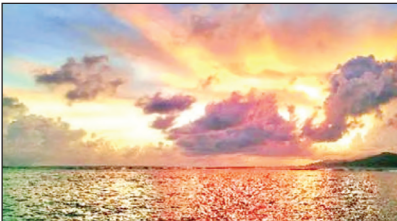
स्काईडॉस का नियंत्रण होगा। अमेरिकी संघीय संचार आयोग (एफसीसी) ने स्काईडॉस को

सीबीएस न्यूज़ का संचालन करने वाली कंपनी पैरामाउंट के साथ विलय को मंजूरी प्रदान कर दी। एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि स्काईडॉस से यह आश्वासन मिलने के बाद इस सौदे को मंजूरी दी गयी है कि नई कंपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध होगी। अध्यक्ष कैर ने बयान में कहा, अमेरिकी अब पारंपरिक राष्ट्रीय समाचार मीडिया पर पूरी तरह, सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने का भरोसा नहीं करते। अब बदलाव का समय आ गया है। इसलिए मैं कभी चिंतित रहे सीबीएस प्रसारण नेटवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव करने की स्काईडॉस की प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं। बताया गया है कि यह 8 अरब डॉलर का सौदा है। यह पैरामाउंट के लिए नई शुरुआत का संकेत है। पैरामाउंट पर दशकों से रेडस्टोन परिवार का नियंत्रण रहा है। टेक अरबपति लैरी एलिसन के बेटे डेविड एलिसन की योजना सौदा पूरा होने पर पैरामाउंट कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की है। हाल के हफ्तों में पैरामाउंट कंपनी ट्रंप प्रशासन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण उथल-पुथल में घिरी रही है। कंपनी ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुकदमे का निपटारा करने के लिए इसी महीने 1.6 करोड़ डॉलर का भुगतान किया। सीबीएस के लेट नाइट होस्ट स्टीफन कोलबर्ट ने कहा कि यह समझौता असल में ट्रंप प्रशासन से सौदे की मंजूरी पाने के लिए एक रिश्तवत थी। एफसीसी की डेमोक्रेटिक कमिशन एना एम. गोमेज़ ने इस मंजूरी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एफसीसी ने पैरामाउंट पर एक निजी कानूनी समझौता कराने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर आंच पहुंची है। चिंताजनक बात यह है कि अब एफसीसी न्यूज़रूम के फैसलों और संपादकीय निर्णयों पर अभूतपूर्व नियंत्रण लागू कर रही है। फिलहाल पैरामाउंट और स्काईडॉस के प्रवक्ता ने इस मंजूरी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

वीज़ा-फ्री एट्री पर करार: पाकिस्तान और बांग्लादेश में आने जाने के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं होगी

ढाका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक बिना किसी वीसा के एक दूसरे के देश में आवाजाही कर सकते हैं। दोनों देशों ने राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-फ्री एट्री पर सहमति जताई है। इसे लेकर भारत अलर्ट हो गया है। यह फैसला ढाका में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी की बैठक में लिया गया। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अनुसार, दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा जरूरतों को हटाने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश पर प्रगति हुई है। दोनों देशों ने इस मामले पर अपनी सहमति दी है। हालांकि, वीज़ा-फ्री व्यवस्था शुरू होने की कोई तारीख नहीं दी गई है। रिपोर्टों में बताया गया कि बैठक में आतंकवाद विरोधी उपायों, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस ट्रेनिंग, नशीली दवाओं पर नियंत्रण और मानव तस्करी से निपटने के प्रयासों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन नई योजनाओं को लागू करने के लिए संयुक्त समिति बनाई जाएगी। इस्लामाबाद से इस टीम का नेतृत्व पाकिस्तान के गृह सचिव खुर्म अचा करंगे। दोनों देशों ने पुलिस अकादमियों के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू करने पर भी सहमति जताई है।

दक्षिण प्रशांत महासागर में समोआ के पास 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की कोई चेतावनी नहीं



अपिया। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित समोआ द्वीप के पास शुक्रवार को 6.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, यह भूकंप समोआ की राजधानी अपिया से करीब 440 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में दर्ज किया गया। भूकंप की गहराई 314 किलोमीटर मापी गई, जो इसे गहरे भूकंपों की श्रेणी में रखता है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। समोआ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ज्यादातर लोगों ने झटके महसूस नहीं किए और न ही किसी तरह की क्षति की जानकारी अभी तक मिली है। सुनामी का कोई खतरा नहीं यूपएस सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भूकंप के बाद किसी भी प्रकार की सुनामी चेतावनी जारी नहीं की है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश वीज़ा-फ्री समझौते से भारत की बढ़ी चिंता, ढाका में बढ़ती दोस्ती पर दिल्ली की पैनी नजर



इस्लामाबाद, 25 जुलाई (एजेंसियां) । पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच राजनयिक व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश पर सहमति ने भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस फैसले के बाद नई दिल्ली अलर्ट मोड पर है और क्षेत्र में बदलते समीकरणों पर पैनी नजर बनाए हुए है। यह महत्वपूर्ण निर्णय ढाका में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया।

पाकिस्तानी गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दोनों देश राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। बयान में कहा गया, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों

के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने इस मामले पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि, इस वीज़ा-मुक्त व्यवस्था के लागू होने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों गृहमंत्रियों की बैठक में सिर्फ वीज़ा ही नहीं, बल्कि आतंकवाद विरोधी उपायों, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, नशीली दवाओं पर नियंत्रण और मानव तस्करी से निपटने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी पक्ष से वहां के गृह सचिव खुर्म अचा करेंगे।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने पुलिस अकादमियों के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रमों

अवैध रूप से कुवैत जा रही 47 नेपाली महिलाओं को दिल्ली हवाईअड्डे से लौटाया गया



नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 47 नेपाली महिलाओं के एक समूह को उस समय रोक दिया गया, जब वो बिना उचित अनुमति के यात्रा वीजा पर कुवैत की यात्रा करने का प्रयास कर रही थीं। इन महिलाओं के पास विदेश में नौकरी के लिए नेपाली दूतावास के नाम का फर्जी अनिवार्य अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिला, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली में नेपाली दूतावास के समन्वय से हिरासत में ले लिया गया। नेपाली दूतावास के उपनियोग प्रमुख डॉ. सुरेन्द्र थापा ने बताया कि सामान्य पूछताछ के बाद इन सभी महिलाओं को सड़क मार्ग से वापस नेपाल भेज दिया गया। रुपन्देही के प्रमुख जिला अधिकारी बासुदेव घिमिरे के अनुसार महिलाओं को नेपाली दूतावास से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रकाश मल्ल के नेतृत्व में गई एक टीम ने नेपाली दूतावास के अन्य कर्मचारियों के साथ सुनौली सीमा से रुपन्देही ले जाया गया। पुलिस के अनुसार आगे की जांच के लिए इन महिलाओं को काठमांडू ले जाया जा रहा है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने पुलिस को मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मानव तस्करी रोधी ब्यूरो को घटना की जांच करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाने का निर्देश दिया है।

अमेरिकी कालेज गेम्स में लागू होंगे संघीय नियम, राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

वाशिंगटन, 25 जुलाई (एजेंसियां) ।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे.

ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी

आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसका

उद्देश्य अमेरिका के सभी कालेजों

के गेम्स (खेलों) में नाम, छवि

और समानता से संबंधित संघीय

नियम लागू करना है। राष्ट्रपति

ने यह कदम इस चिंता के बाद

उठाया कि अनियंत्रित खर्च और

राज्यों के नाम, छवि और

समानता कानूनों ने निष्पक्ष

प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है।



व्हाइट हाउस ने यह ब्यौरा उपलब्ध कराया है। व्हाइट हाउस के विवरण में कहा गया है कि राष्ट्रपति का यह कार्यकारी आदेश छात्रवृत्ति, महिला

और गैर-राजस्व खेलों की रक्षा करेगा। यह आदेश कालेज एथलीटों को तीसरे पक्ष के भुगतान पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है, जबकि ब्रांडिंग के लिए

विज्ञापनों की अनुमति देता है।

राष्ट्रपति का मानना ​​है कि एथलीटों की भर्ती के लिए प्रोत्साहन भुगतान प्रतिस्पर्धा के संतुलन के लिए खतरा पैदा करते हैं। इससे छोटे खेलों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। इस आदेश के अनुसार, 2024-25 सीजन के दौरान 125 मिलियन डॉलर या उससे अधिक राजस्व वाले एथलेटिक विभागों को महिलाओं और गैर-राजस्व खेलों में छात्रवृत्ति और रोस्टर स्थानों का विस्तार करना होगा। 50 मिलियन डॉलर से 125 मिलियन डॉलर के बीच आय वाले विभागों को यथास्थिति बनाए रखनी होगी। 50 मिलियन डॉलर से कम आय वाले विभागों को गैर-राजस्व खेलों के अवसरों में कटौती नहीं करनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कालेज खेलों का देश में विशिष्ट स्थान है। यह

खिलाड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही कई समुदायों में पारिवारिक गतिविधियों, मनोरंजन और संस्कृति का अमिट हिस्सा बनते हैं। इन खिलाड़ियों को भी फुटबॉल खिलाड़ियों जैसा मान-सम्मान और लाभ मिलना चाहिए। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओलंपिक टीम ने कुल 126 पदक अर्जित किए। टीम लगातार आठवें ओम्पिकलीन ओलंपिक खेलों की समग्र पदक गणना में अग्रणी रही।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेजोड़ सफलता के अलावा, कॉलेज के एथलीट स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं। सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में महिला अधिकारियों का

एक बड़ा हिस्सा किशोरावस्था के दौरान खेलों में शामिल रहा है। इस मामले में कॉलेज खेलों में हिस्सा लेने वालों में कई उद्योगपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि अमेरिका की कॉलेजिएट एथलेटिक्स प्रणाली हमारे राष्ट्र की सफलता के प्रेरक नेताओं को तैयार करने में एक अभिन्न भूमिका निभाती है।

ट्रंप ने कहा कि कालेज गेम्स के नियमों के खिलाफ हालिया मुकदमों की वजह से इस तरह के कार्यकारी आदेश की जरूरत महसूस की गई। यह कार्यकारी आदेश कालेज गेम्स को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। प्रशासन सभी कॉलेज खेलों को संरक्षण प्रदान करेगा। 2025-2026 एथलेटिक सीजन में इसका प्रभाव देखा जा सकेगा।

बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार पुल प्रशासन ने ढहाया



ढाका, 25 जुलाई (एजेंसियां) ।

दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश

के बारिसल डिवीजन के

पिरोजपुर जिला में एक पुल

के निर्माण में घटिया सामग्री

का प्रयोग होने पर ढहा दिया

गया। मदरा बाजार रोड पर

ठेकेदार के माध्यम से इस

पुल को तैयार कराया गया

था। ठेकेदार को इसके लिए

5.73 करोड़ टका का

भुगतान किया गया।

ठेकेदार ने यह काम किसी

दूसरे को सौंप दिया था।

खबर के अनुसार, स्थानीय निकाय अभियांत्रिकी विभाग (एलजीडी) से लोगों ने शिकायत की थी कि जलाबाड़ी यूनियन के मदरा बाजार रोड पर स्थित यह पुल कभी भी गिर सकता है। इसके निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। विभाग को जांच में बड़ी खामियां मिलीं। इसके बाद पुल को गिरा दिया गया। इस घटना के बाद बांग्लादेश में सरकारी निर्माण परियोजनाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। स्थानीय नागरिकों के गुस्से को देखते हुए एलजीडी को इस संरचना को गिराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पुल का ठेका 29 दिसंबर, 2021 को पिरोजपुर एलजीडी ने एक ठेकेदार फर्म को दिया था। इसका अनुबंध मूल्य 5.73 करोड़ टका था। अनुबंध के अनुसार, इसका निर्माण 28 दिसंबर, 2022 तक पूरा होना था। मुख्य ठेकेदार ने यह काम दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया। उसने निर्माण मानकों का पालन नहीं किया और परियोजना समय-सीमा का उल्लंघन भी किया। दूसरे ठेकेदार खोकोन मिया ने दावा किया कि कंक्रीट के काम के बाद किसी ने बिना अनुमति के सेंटिंग हटा दी, जिसके कारण यह नौबत आई। उप जिला इंजीनियर मोहम्मद रायसुल इस्लाम ने कहा कि पूरे स्लैब को तोड़कर नए सिरे से पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य ठेकेदार को सौंप दिया। उसने निर्माण मानकों का पालन नहीं किया और परियोजना को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है।

ओली सरकार को झटका, राष्ट्रपति का संवैधानिक परिषद विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार

काठमांडू, 25 जुलाई (एजेंसियां) ।

प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार को उस समय तड़ा झटका लगा जब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद (कर्तव्य, कार्य, अधिकार और प्रक्रिया) अधिनियम, 2006 से संबंधित संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा को वापस कर दिया है। राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार, विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए गुरुवार को वापस भेज दिया गया था। पोखरेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को मूल सदन को यह कहते हुए वापस कर दिया कि प्रस्तावित संशोधन संविधान की भावना और सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रथाओं के विपरीत है। राष्ट्रपति की तरफ से यह कदम संविधान के अनुच्छेद 113 (3) के तहत उठाया गया है।

प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक 15 जुलाई की प्रमाणिकरण के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचा था। एक सप्ताह की लंबी समीक्षा के बाद, राष्ट्रपति पौडेल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करने का विकल्प चुना और इसे संसद के निचले सदन को वापस कर दिया।

नेपाल के संविधान की अनुच्छेद 113 राष्ट्रपति



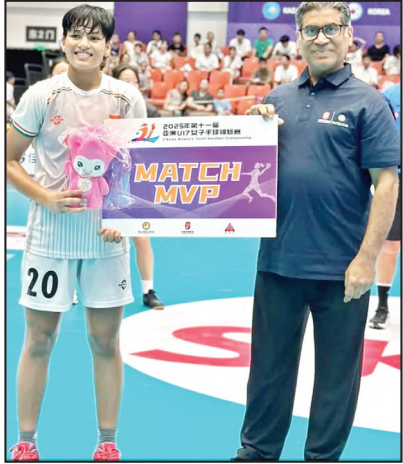
को किसी भी विधेयक (धन बिलों को छोड़कर) को यदि वह इसे पुनर्विचार के लिए आवश्यक समझते हैं तो 15 दिनों के भीतर मूल सदन को वापस भेजने की अनुमति देता है। प्रधानमंत्री को पहल पर सदन से पारित हुए इस विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस का एक बड़ा खेमा इसके विपक्ष में दिखा। नेपाली कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की थी कि निचले सदन द्वारा पारित संशोधन में नेशनल असेंबली का संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इसके पुनर्मूल्यांकन को आवश्यकता है। नेपाल के संविधान में छह सदस्यीय संवैधानिक परिषद की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रीय

सभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश और प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लौटाय गए विधेयक में एक प्रावधान शामिल था जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक निकायों में नियुक्तियां परिषद के भीतर सर्वसम्मति के माध्यम से की जानी चाहिए। यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, तो निर्णय बहुमत से लिए जा सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में) और वर्तमान में सेवारत सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत शामिल है। इसमें संशोधन करते हुए सभी राजनैतिक और संवैधानिक नियुक्ति करते समय सिर्फ प्रधानमंत्री और कोई भी एक सदस्य चाहे तो इस परिषद के तरफ से कोई फैसला ले सकते हैं। गठबंधन बचाने के लिए तो दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया लेकिन ओली की नीयत को देखते हुए कांग्रेसी सांसदों और नेताओं ने ही राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर उसे अस्वीकृत करवाया है। इस समय संवैधानिक परिषद में प्रधानमंत्री ओली अल्पमत में हैं। उनके अलावा सिर्फ प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही उनके पक्ष में हैं, बाकी डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दल के नेता सभी उनके विरोधी ही हैं।



न्यूज़ ड्रीफ़

वाराणसी की हैडबॉल खिलाड़ी नैना यादव चीन में मोस्ट वेल्थ्युबल खिलाड़ी घोषित



वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद की प्रतिभाशाली हैडबॉल खिलाड़ी नैना यादव को चीन के जिंघांगशन शहर में आयोजित 11वीं एशियन यूथ वीमेन हैडबॉल चैंपियनशिप 2025 में बीते गुरुवार की शाम मोस्ट वेल्थुबल खिलाड़ी घोषित किया गया। नैना यादव भारतीय टीम की उप कप्तान भी हैं। इसी प्रतियोगिता में वाराणसी की कोमल राय भी हिस्सा ले रही हैं। दोनों खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन पर उनके कोच और परिजनों ने खुशी जताई है। दोनों खिलाड़ी यहां परमानंदपुर स्थित विकास इंटर कालेज की 11वीं की छात्रा हैं ज कालेज के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. सिंह ने यह जानकारी दी है। चीन में आयोजित एशियन यूथ वीमेन हैडबॉल चैंपियनशिप उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के साथ पूरी भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामना दी है। दोनों खिलाड़ी यहां बाबू आरपन सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परमानंदपुर में डॉ आशा सिंह की देखरेख में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। बताते चलें गांव के बेहद गरीब परिवार की दोनों बेटियां पहली बार भारतीय महिला हैडबॉल टीम में भागीदारी कर रही हैं। दोनों के पिता राजगीर मिरसी (भवन निर्माण श्रमिक) हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ बेहतरों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे हैं। परिजनों के साथ साथी खिलाड़ियों को पूरी उम्मीद है कि नैना और कोमल चीन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और जिले का नाम रोशन करेंगी।

आर्सेनल ने वेलेंसिया के डिफेंडर क्रिस्थियन मोस्केरा के साथ किया करार



लंदन। प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल ने गुरुवार को स्पेनिश क्लब वेलेंसिया के डिफेंडर क्रिस्थियन मोस्केरा के साथ करार की घोषणा की। स्पेन की अंडर-21 टीम के इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को लगभग 13 मिलियन पाउंड (प्रदर्शन आधारित ऐड-ऑन सहित) की शुरुआती फीस पर साइन किया गया है। उन्होंने पांच साल का अनुबंध किया है, जिसमें एक साल का अतिरिक्त विकल्प शामिल है। इस डील के साथ आर्सेनल का इस समर ट्रांसफर विंडो में खर्च लगभग 140 मिलियन पाउंड (करीब 189 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है। 21 वर्षीय मोस्केरा, जो हाल ही में आर्सेनल के पांचवें साइनिंग बने हैं, टीम के प्रमुख डिफेंडरों विलियम सलीबा और गैब्रियल को कवर देंगे। हालांकि, वह डिफेंस की किसी भी पोजीशन पर खेलने में सक्षम हैं। पिछले सीजन में मोस्केरा ने वेलेंसिया के लिए 41 मुकाबले खेले थे। उन्होंने अब आर्सेनल की सिंगापूर और हांगकांग की प्री-सीजन टूर के लिए टीम को जॉइन कर लिया है। गौरतलब है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग में लगातार तीन बार उपविजेता रहा है और वह अपना 2025/26 सीजन का पहला मुकाबला 17 अगस्त को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगा। इस बीच, क्लब स्पोर्ट्स लिखन के स्ट्राइकर विक्टर ग्योक्रेस को साइन करने की भी उम्मीद कर रहा है।

टी20 में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने ईश सोढ़ी

हरारे। न्यूजीलैंड के भारतीय मूल के स्पिनर ईश सोढ़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ में चार विकेट लेने के साथ ही टी20 में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए। सोढ़ी टिम साउथी और राशिद खान के बाद टी20 प्रारूप में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह तीसरे और न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। ईश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में केवल 4 ओवर में ही 12 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके इस शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड की टीम ने 60 रनों से मैच जीत लिया। गौरतलब है कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड टिम साउथी के नाम है। साउथी ने 126 मैचों में 164 विकेट लिए हैं। वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान हैं। इस कलाई स्पिनर ने केवल 96 मैचों में 161 विकेट लिए हैं।

शनिवार, 26 जुलाई, 2025

बंगलूर



फिडे महिला विश्व कप में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी बनेगा विजेता, हम्पी की दिव्या से टक्कर

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

स्टार महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख शनिवार को होने वाले फिडे महिला विश्व कप फाइनल में एक-दूसरे के सामने होंगी जिससे पहली बार इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी विजेता बनेगा। इस प्रतियोगिता के इतिहास में यह पहली बार है जब दो भारतीय फाइनल में आमने-सामने होंगी। हम्पी और देशमुख दोनों ने फाइनल में पहुंचकर अगले साल होने वाले महिला कैडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम्पी खिताब की प्रबल दावेदार बड़े मुकाबलों में खेलने के अपने अनुभव के आधार पर हम्पी फाइनल में हमवतन देशमुख के खिलाफ प्रबल

दावेदार के रूप में उतरेगी। हम्पी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चीन की टिंगजी लैई को टाईब्रेकर में हराकर जीत हासिल की जबकि देशमुख ने अंतिम-चार चरण के दूसरे गेम में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की हो ज़ोंगयी टैन को हराया। 38 वर्षीय ग्रैंडमास्टर हम्पी विश्व महिला रैंपिड टूर्नामेंट की विजेता थीं और हाल में महिला ग्रा प्री में भी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रही। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। पिछले कई वर्षों में उनका जज्बा और दृढ़ संकल्प जरा भी कम नहीं हुआ है। हम्पी ने फिडे वेबसाइट से कहा, शतरंज प्रेमियों के लिए यह सबसे खुशी के पलों में से एक है क्योंकि अब

खिताब निश्चित रूप से भारत के पास जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के रूप में कल का मैच भी काफी कठिन होगा। दिव्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम्पी से आधी उम्र की अंतरराष्ट्रीय मास्टर देशमुख इस प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में शामिल तीन खिलाड़ियों को हराकर उलटफेर कर चुकी हैं। उनका पहला शिकार चीन की दूसरी वरीयता प्रास जिनर जू थी जिन्होंने डी हरिका को बाहर कर दिया था। सेमीफाइनल में देशमुख ने टैन को हराया नागपुर की 19 वर्षीय देशमुख ने सेमीफाइनल में चीन की पूर्व महिला विश्व चैंपियन ज़ोंगयी टैन को हराया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के बाद कहा, मुझे बस

थोड़ी नॉड और थोड़ा खाना चाहिए। इन दिनों मैं काफी चिंतित हूं। देशमुख ने अपनी सेमीफाइनल बाजी के बारे में कहा, मुझे लगता है कि मैं और बेहतर खेल सकती थी। एक समय मैं जीत रही थी और फिर चीजें मुश्किल हो गईं। मुझे लगता है कि मैंने बीच में गलती कर दी, वरना मुझे और भी आसान जीत मिल सकती थी। मुझे लग रहा था कि यह झूड़ा रहेगा। पर अंत में मैं भाग्यशाली रही। टूर्नामेंट के विजेता को मिलेगी मोटी रकम हम्पी को ग्री-क्राउटर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन स्विट्जरलैंड की एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक ने टाईब्रेकर तक खींचा और इसके बाद उन्होंने युक्सिन सोंग के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम चार मैचों की श्रृंखला के लिए करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा

15 से 21 अगस्त तक पर्थ हॉकी स्टेडियम में होंगे मुकाबले

नई दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगस्त में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह पर्थ हॉकी स्टेडियम में 15 से 21 अगस्त तक चार मैचों की सीरीज खेलेगी। यह सीरीज भारत के लिए एशिया कप 2025 की तैयारियों का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है। आठवीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम का सामना छठी रैंकिंग वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम से होगा। मुकाबले 15, 16, 19 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। हाल ही में दोनों टीमों एफआईएच प्रो लीग 2024-25 के तहत यूरोप में आमने-सामने आई थीं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दोनों मैचों में 3-2 से हराया था। हालांकि, इससे पहले भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर इतिहास रच दिया था-यह ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की 1972 म्यूनिख खेलों के बाद पहली जीत थी। पिछले कुछ वर्षों में भले ही मुकाबले कड़े रहे हों, लेकिन समग्र आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। साल 2013 से अब तक दोनों टीमों के बीच 51 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 35 मैच जीते हैं, भारत ने 9 और 7 मुकाबले हारे हैं। यह सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले हिरो एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। यह टूर्नामेंट एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का मौका देगा, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत की रणनीति में एक बड़ा कदम है। इस दौरान को लेकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रैग फुल्टन ने कहा, यह दौरा हमारे लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह एशिया कप से ठीक पहले आ रहा है। भले ही ये दोस्ताना मैच हों, लेकिन हमारे लिए ये तैयारी का अहम हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हमारी हर स्तर पर परीक्षा लेगा, और यही चुनौती हमें चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा, हमने हाल ही में 10 दिनों का ट्रेनिंग कैंप पूरा किया है और टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। पहले दो मैचों का इस्तेमाल हम संभावित खिलाड़ियों के चयन के लिए करेंगे।



अगले माह होगा रोमन रेंस और जे उसो का ब्रेकर और ब्रॉन्सन से मुकाबला

सेन डियागो। डब्ल्यू डब्ल्यूई में अगले महा अगस्त में रेसलर रोमन रेंस और जे उसो की टीम का मुकाबला ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड से होगा। यह मुकाबला 2 या 3 अगस्त को समरस्लेम में होगा। पॉल हेमैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इस मुकाबले के बारे में बताया है। उन्होंने रोमन रेंस और जे उसो को चेतावनी भी दी है। हेमैन ने रोमन रेंस को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह मुकाबला उनके लिए बेहद कठिन रहेगा। हेमैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, रोमन किसी भी दिन मुकाबला करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की ओर से रोमन रेंस और जे उसो ने मुकाबले की चुनौती स्वीकार की है। रोमन ने इससे पहले हेमैन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि हेमैन ने उन्हें द ट्राइबल चीफ नहीं बनाया है। रेंस ने कहा कि वह द ट्राइबल चीफ इसलिए हैं क्योंकि फैंस उन्हें अभी भी मानते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि वह यहां के नए विंग डॉग हैं। रेंस और ब्रेकर के बीच मारपीट भी हुई थी। जे उसो ने आकर रोमनको बचाया। इसके बाद रेंस ने समरस्लेम के लिए चुनौती दी। जे उसो इस मुकाबले में रोमन रेंस के पार्टनर होंगे।



प्रीमियर लीग ट्रॉफी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर

लंदन में प्रीमियर लीग ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर।

यश पर अब एक नाबालिग ने लगाया बलात्कार का आरोप

मुम्बई, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

क्रिकेटर यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही यौन शोषण मामले में फसे यश पर अब जयपुर में एक नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया है। आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के क्रिकेटर यश पर इससे पहले गाजियाबाद में एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में वह कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं हालांकि वह अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में गाजियाबाद मामले में यश की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी पर अब जयपुर में उनके खिलाफ जो मामला दायर हुआ है उससे उनका करियर भी खतरे में आ गया है।



उत्तर 17 साल की नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यश के खिलाफ सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में नाबालिग पीड़िता द्वारा बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि यश ने पेशेवर क्रिकेट में बेहतर भविष्य का वादा करते हुए उसका दो साल तक शोषित किया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता क्रिकेट के जरिये ही यश के संपर्क में आयी थी। ऐसे में यश ने उसे बेहतर क्रिकेट करियर बनाने का झांसा देते हुए दो साल तक बलात्कार किया। रिपोर्ट में आईपीएल 2025

का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि यश दयाल ने जयपुर में हुए मैच के दौरान पीड़िता को एक होटल में बुलाया और उसका शोषण किया। लंबे समय तक चुपची, भावनात्मक ब्लैकमेल और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बाद पीड़िता ने अंत में उसके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। जयपुर पुलिस ने आगे बताया कि जब बलात्कार की पहली घटना तब हुई थी जब पीड़िता 17 साल की नाबालिग थी, इसलिए यश के खिलाफ पास्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाये जाने पर यश को लंबे समय की सजा होना तय है।

ऋषभ के चोटिल पैर को निशाना बनाने वाले स्टोक्स पर मड़के लोग

मैनचेस्टर, 25 जुलाई (एजेंसियां)।

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के बाद भी बल्लेबाजी के लिए उतरे। उनके इस जज्बे की जहां लोगों ने प्रशंसा की और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की कड़वी आलोचना की। स्टोक्स इस मैच में जानबूझकर ऋषभ के चोटिल पैर पर यॉर्कर गेंदें कर रहे थे। वहीं जब ऋषभ ने एक रन लिया तब भी स्टोक्स ने बहुत ही ध्यान से उनके पैर के उस पंजे को देखा जिसमें फ्रैक्चर हुआ था। उन्होंने टूटी अंगुली को लथ्थ कर लगातार यॉर्कर गेंदें फेंकीं। ऋषभ तब भी बिना डरे जमे रहे और उन्होंने एक पैर से खेलते हुए आक्रामक शॉट लगाये। जोफ्रा आचर ने भी उनके पैर पर ही निशाना साधर पर इस बल्लेबाजी ने शानदार छक्का लगा दिया। इस प्रकार किसी बल्लेबाज के चोटिल पैर को ही गेंद से टारगेट करने की स्टोक्स की



रणनीति की सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हुई है। लोगों ने कहा कि खेल है, खेल ही रहने दो। क्या आउट करने के लिए फ्रैक्चर पर ही टारगेट करना जरूरी था यह आउट करने की

रणनीति थी या विरोधी को जानबूझकर और ज्यादा चोटिल करने की बेहद शर्मनाक कोशिश साथ ही कहा कि स्टोक्स ने क्रिकेट भावना, खेल भावना, जेंटलमेन गेम जैसे बातों का अपमान

सचिन तेंदुलकर सहित दिग्गजों ने ऋषभ पंत के इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में चोटिल होने के बाद भी बल्लेबाजी के लिए उतरने पर उनके जज्बे को सलाम किया है। ऋषभ जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो टीम मुश्किल हालातों में थी पर उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलकर उससे 358 रनों के अछे स्कोर तक पहुंचाया। पहली पारी में जब वह पहले दिन बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके पैर पर एक तेज गेंद लगी थी। क्रिस वोक्स की ये गेंद सीधे ही उनके पैर के अंगुठे पर लगी जिससे उसमें फ्रैक्चर हो गया। मैदान से उनको एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाना पड़ा और डॉक्टरों ने उनको करीब छह सप्ताह तक खेल से दूर रहने को कहा पर इसके बाद भी वह दूसरे दिन पेन क्लिपर लेकर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने लंगड़ाते मेजबान इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों का पूरे साहस से सामना किया। तेंदुलकर ने इस साहसिक पारी को देखकर कहा, मजबूती का मतलब है दर्द के बावजूद खेलना और उससे ऊपर उठना। ऋषभ ने चोट के साथ वापस मैदान में आकर और ऐसा प्रदर्शन करके जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया है।

किया है।

अभी दो दिन पहले ही पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने कहा था कि इंग्लैंड सहित कुछ टीमें खेल भावना शब्द का इस्तेमाल अपनी सुविधा के

अनुसार करती हैं। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए हैं। फ्रैक्चर होने के बावजूद ऋषभ ने दूसरे दिन बल्लेबाजी की और 54 रन बनाकर आउट हुए।

कल रवि योग में मनाई जाएगी हरियाली तीज



नीतिका शर्मा
ज्योतिषाचार्या एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर
श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर, अजमेर

हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ स्था नों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोम्नी वर पाने के लिए भी तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती है और सावन के लोकगीत गाकर इस त्यौहार की खुशियां मनाती हैं। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई को रात 10:41 मिनट पर शुरू होगी और यह तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 मिनट से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 मिनट तक रहेगा। रवि योग में पूजापाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्वम होता है इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से दो तिथि पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं।

सनातन धर्म में हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है हरियाली तीज है, जो देशभर में मनाई जाती हैं। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता हैं। हरियाली तीज सावन मास का सबसे

महत्वपूर्ण पर्व हैं। महिलाएं इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करती हैं। हरियाली तीज सौंदर्य और प्रेम का पर्व हैं। यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता हैं। यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का पर्व हैं। हरियाली तीज का जब पर्व आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती हैं। पेड़ पौधे उजले उजले नजर आने लगते हैं। हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता हैं। हरियाली तीज या श्रावणी तीज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं।

हरियाली तीज पर शुभ योग

इस साल हरियाली तीज के अवसर पर रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 मिनट से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 मिनट तक रहेगा। रवि योग में पूजापाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है।

शादी के बाद की पहली तीज है खास

हरियाली तीज की पूजा दोपहर बाद ही होती है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, जो कि जरूरी रस्म होती है। इसके अलावा घेवर खाती हैं। असल में इस पर्व का नाम मधुश्रवा हरियाली तीज है। यह नाम इसीलिए पड़ा कि इसमें मधु टपकता है। मिष्ठान खाने को मिलते हैं। खासकर नवविवाहिता की पहली तीज पर खास आयोजन होता है। ससुराल से उसके लिए सिंधारा आता है। इसमें घेवर, फेनी, कपड़े, मिष्ठान, फल आदि आते हैं।

हरियाली तीज परम्पराएं

सावन के माह में आने वाले त्यौहारों को नवविवाहित स्त्रियों

के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परम्परा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी गई है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती हैं। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती हैं और लोक गीत पर नृत्य करती हैं।

पूजा विधि

शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था इसलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा-अर्चना करती हैं। हरियाली तीज के दिन साफ-सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी-देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किये जाते हैं।

ऐसे मिला था देवी पार्वती को तप का फल

भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती! इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था। उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को में मन वांछित फल देता हूं। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती या सुनती है वहअखंड सौभाग्यवती होती है।

हरियाली तीज पर महिलाएं रखें इन बातों का विशेष ख्याल

✱ इस महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हरी चूड़ियां भी।

✱ हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को सोलह श्रृंगार का सामान अर्पित करें और शादीशुदा महिलाएं खुद भी सोलह श्रृंगार करें।

✱ जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उन्हें भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। खाने पीने से व्रत अधूरा माना जाता है।

✱ साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियां भूलकर भी न पहनें।

हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि

हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

इसके बाद सबसे पहले अपने पूजाघर को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर पूजा घर को पवित्र करें।

इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती और भगवान

शिव की प्रतिमा स्थापित करें।

इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें की माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बालू से बनी होनी चाहिए। अगर बालू की प्रतिमा न हो तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं।

इसके बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती की आवाहन करें और इसके बाग शिवजी का अभिषेक करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।

इसके बाद हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें और अंत में शिव पार्वती की आरती करें और हाथ जोड़कर पूजा में हुई कोई भी भूल चूक के लिए माफी मांगें।

अगले दिन बालू से बनी प्रतिमा को किसी नदी में विसर्जित कर दें।

तीज पर व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी नियमों करें पालन

सावन का महीना हरियाली, उत्सव और नारी शक्ति की आभा से जगमगाता है। खासतौर पर हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख-शांति के लिए व्रत रखती हैं। सजी-धजी महिलाएं, हाथों में मेहंदी और झूलों की रौनक - तीज का दृश्य किसी पर्व से कम नहीं। लेकिन इस व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है।

निर्जला व्रत का पालन करें

तीज का व्रत बिना पानी के (निर्जला) रखा जाता है। कई महिलाएं अनजाने में चाय या फल ले लेती हैं, जिससे व्रत टूट सकता है। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो बिना पानी के व्रत रखें। अस्वस्थ या गर्भवती होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें।

व्रत के दिन हरा रंग पहनना शुभ

हरे रंग को हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता



है। काले और सफेद रंग से बचें और हरा, लाल या पीला रंग पहनें।

सोलह श्रृंगार है जरूरी

बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और मेहंदी जैसी सुहाग की निशानियों के बिना तीज का व्रत अधूरा माना जाता है।

नुकीली चीजों से परहेज करें

सुरई-कैंची जैसी चीजोंका उपयोग न करें। तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बाधित हो

सकती है।

मन को शांत रखें

इस दिन झगड़ा या बहस करने से बचें। भक्ति और भजन में समय बिताएं, जिससे मन और व्रत दोनों पवित्र बने रहें।

दिन में न करें सोना

हालांकि शरीर थक सकता है, फिर भी दिन में सोना वर्जित माना गया है। पूजा और भजन करना अधिक फलदायी होता है।

व्रत के बाद करें दान

व्रत पूर्ण होने के बाद अन्न, जल और वस्त्रों का दान करना आवश्यक है। यह व्रत को पूर्णता देता है और पुण्य में वृद्धि करता है। हरियाली तीज सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री श्रद्धा, शक्ति और सौभाग्य का पर्व है। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए किया गया यह व्रत आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है।

भाय्यनगर कांवड़ सेवा संघ की 28वीं भव्य कांवड़ यात्रा कल

हैदराबाद–सिकंदराबाद में शिवभक्ति का संगम

हजारों कांवड़िये करेंगे जलाभिषेक

भाय्यनगर कांवड़ सेवा संघ द्वारा आयोजित होने

वाली 28वीं भव्य पैदल कांवड़ यात्रा 2025 का आयोजन इस वर्ष 27 जुलाई को बड़े उत्साह और श्रद्धा

के साथ किया जाएगा। यह कांवड़ यात्रा चारमीनार स्थित श्री महादेव मंदिर से आरंभ होकर मंचीरबुला स्थित ब्रह्मसूत्र ऑकारेश्वर स्वामी देवालयम (प्राचीन शिव मंदिर) तक जाएगी।

भाय्यनगर कांवड़ सेवा संघ के अध्यक्ष मांगेराम तायल ने बताया कि यह यात्रा अपनी भव्यता और विशेषता के लिए जानी जाती है, जिसमें हर वर्ष हजारों से अधिक कांवड़िये शामिल होते हैं। कांवड़धारी हरिद्वार की हर की पौड़ी से लाए गए पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे।

सुरक्षा और अनुशासन के लिए विशेष नियम

संघ के अध्यक्ष मांगेराम तायल ने बताया कि सभी कांवड़ियों और शिवभक्तों की सुरक्षा और यात्रा की सुचारू रूप से पूर्णता के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। उन्होंने सभी से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

कांवड़ यात्रा के मुख्य नियम

चमड़े की कोई वस्तु न पहनें – कांवड़ियों के शरीर पर जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स आदि किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु नहीं होनी चाहिए।

सात्विक भोजन ही ग्रहण करें – केवल संघ द्वारा उपलब्ध कराया गया सात्विक भोजन लें। बाहर से

केवल पानी लेना अनुमत है।

डीसीएम रस्सी के अंदर चलें – संघ द्वारा डीसीएम (वाहन) में बांधी गई रस्सी के अंदर सभी को चलना

होगा। शिव का जाप करते हुए अपनी पंक्ति में अनुशासित रूप से चलें।

क्रम संख्या का पालन करें – सभी कांवड़ियों को क्रम संख्या के अनुसार छोड़ा जाएगा। खड़ी कांवड़ उठाना आस्था का प्रतीक है, अतः अपने क्रम का धैर्यपूर्वक इंतजार करें।

संघ की व्यवस्था में बाधा न डालें – डीसीएम के आगे जाने या भीड़ में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास न करें।

सुविधाओं का सही उपयोग करें – पानी की गाड़ियां, स्नान और लघुशंका के लिए सुलभ की गाड़ियां तथा पानी के टैंकर उपलब्ध रहेंगे।

संघ की अपील – श्रद्धा और सुरक्षा दोनों जरूरी मांगेराम तायल ने कहा, संघ हमेशा यही प्रयास करता है कि किसी भी कांवड़धारी या शिवभक्त को कोई परेशानी न हो। लेकिन सभी को अपनी और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। किसी भी अग्रिय घटना के लिए संघ जिम्मेदार नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि सभी अनुशासन का पालन करते हुए यात्रा का आनंद लेंगे और महादेव की भक्ति में लीन रहेंगे।

मांगेराम तायल
अध्यक्ष
भाय्यनगर कांवड़ सेवा संघ

शनिवार को इनमें से कोई एक चीज जरूर खाएं

शनिदेव चमका देंगे भाग्य, जल्दी पाएंगे लाभ और तरक्की

शनिवार के स्वामी देवता भगवान शनि को माना जाता है। शनि के बारे में ज्योतिषशास्त्र में कहा गया है कि यह भाग्य को चमका भी सकते हैं और नाराज होने पर राजा को भी रंक बना देते हैं। ऐसे में शनि महाराज को अनुकूल बनाए रखना हर किसी के लिए जरूरी माना गया है। चाहे आपकी साढ़े साती, ढैय्या नहीं भी चल रही हो या शनि की दशा के प्रभाव में भी आप नहीं हो लेकिन फिर भी आपको शनि के उपाय हर शनिवार को जरूर करना चाहिए ताकि जब शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या दशा आए तो शनिदेव आपका अहित न करें साथ ही प्रसन्न होकर आपका सोया भाग्य चमका दें और तरक्की दिलाएं। इसके लिए कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो खानपान से जुड़े हुए हैं। तो आप व्रत करने की बजाय रुचिकर भोजन का आनंद लेते हुए भी शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते है, तो आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन किन-किन चीजों को खाने से शनिदेव कृपा बरसाते हैं और आपको तरक्की दिलाते हैं।

शनिवार को खिचड़ी खाने के लाभ

शनिवार के दिन बहुत से लोग खिचड़ी जरूर खाते हैं। अगर आप अब तक ऐसा नहीं करते हैं तो शनिवार के दिन खिचड़ी खाने का यह फायदा जानेंगे तो आप भी इसे आदत बना लेंगे। ऐसी मान्यता है कि उड़द की दाल जो शनिदेव से संबंध रखता है



उससे खिचड़ी बनाकर खाने से और शनिदेव को भोग लगाने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और आपके ऊपर से शनि का प्रकोप भी दूर हो जाता है। अगर उड़द दाल नहीं हो तो आप जिस भी दाल को पसंद करें उससे भी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। यह भी लाभकारी होता है।

शनिवार को भुने हुए चने खाने का फायदा

आपने देखा होगा कि बहुत से लोग शनिवार के दिन बंदरों को काले चने खिलाते हैं। यह उपाय भी शनि के प्रकोप को कम करता है। लेकिन आप बंदरों को चने खिलाने के साथ-साथ भुने हुए काले चने खुद भी खाएं तो यह और भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार काले चने का संबंध शनिदेव से है। इसे

खाने से शनि ग्रह से संबंधित जो शारीरिक दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। और शनिदेव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव होता है।

शनिवार को काले तिल खाने के फायदे

काले तिल को भगवान विष्णु से उत्पन्न माना जाता है। काले तिल के विषय में कथा है कि यह शनि महाराज को भी बहुत प्रिय है जो भक्त नियमित शनिवार के दिन काले तिल से पीपल की पूजा करता है और शनिवार के दिन काले तिल का प्रसाद शनि महाराज को अर्पित करता है और काले तिल का सेवन करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और शनि महाराज भी अपने ऐसे भक्त पर प्रसन्न होकर तरक्की दिलाते हैं।

शनिवार को काला जामुन खाने के फायदे

शनिवार के दिन आप काले जामुन का सेवन करें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जामुन सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। यह शुरार सहित कई रोगों में लाभदायक होता है। जब जामुन का मौसम समाप्त हो जाए तो आप मिठाई वाला काला जमुन भी खा सकते हैं। लाल किताब के उपाय में कीए और कुत्ते को काला जामुन खिलाना भी ग्रहों के दोष को दूर करने वाला बताया गया है।

फिल्म सैयारा ने दुनियाभर में रचा इतिहास

आमिर-अजय देवगन की फिल्मों को पछाड़ बनी तीसरी ब्लॉकबस्टर

मो हित सूरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा इन दिनों दर्शकों और सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की प्रेश जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वहीं, फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई ने भी सबको चौंका दिया है। अब इस फिल्म ने एक और बड़ा

रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे जानकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे।

दरअसल, फिल्म ने अपने पहले 7 दिनों में ही आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म 'सितारे जमीन पर' के लाइफटाइम नेट कलेक्शन 166.118 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, अब इसने अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'रेड 2' को भी पछाड़ दिया है।

सैयारा ने तोड़ा अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म का रिकॉर्ड

डालपळश्रज़ की रिपोर्ट के अनुसार, सैयारा ने सोमवार को 24 करोड़, मंगलवार को 25 करोड़ और बुधवार को 21 करोड़ की कमाई करते हुए सिर्फ 7 दिनों में 177.13 करोड़ का शानदार नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 248.50 करोड़ पहुंच चुकी है।

इसके साथ ही फिल्म ने रेड 2 के इंडिया कलेक्शन 173.44 करोड़ और वर्ल्डवाइड 237.46 करोड़ को पार करते हुए साल 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। यह 'सैयारा' के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है।

तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बनी सैयारा

इसके अलावा सैयारा अब तक की बंपर ओपनिंग करने वाली तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। 2025 में 'छावा', 'सिकंदर' और 'हाउसफुल 5' जैसी बड़ी फिल्मों के बीच, 'सैयारा' ने अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म के ओपनिंग डे पर म्यूजिक, ट्रेलर और सोशल मीडिया पर वायरल टाइटल ट्रेंड ने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इसे जबरदस्त ओपनिंग मिली।

स्मृति ईरानी के कमबैक पर अनुपमा सोलंकी बोलीं

उनके शो देखकर बड़ी हुई आज भी भावुक हो जाती हूं



अ भिनेत्री अनुपमा सोलंकी खुश हैं कि स्मृति ईरानी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। अनुपमा ने बताया कि वह उनके शो बचपन से देखती आई हैं, शो का थीम सॉन्ग सुन वो आज भी भावुक हो जाती हैं। अनुपमा ने बताया कि वह स्मृति के शो देखकर बड़ी हुई।

स्मृति ईरानी की टीवी पर वापसी के बारे में पूछे जाने पर अनुपमा ने कहा, यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। इतने सालों बाद उन्हें फिर से कास्ट किया गया है, जैसे एकता कपूर ने पहले किया था। मैं 'कहानी घर घर की', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कसीटी जिंदगी की' देखकर बड़ी हुई हूं। आज भी उन शो के थीम सॉन्ग सुनकर भावुक हो जाती हूं।

'जागृति - एक नई सुबह' फेम अभिनेत्री ने आगे कहा, हाल ही में मैंने 'क्योंकि' के गाने पर एक रील बनाई। काश, मैं इस वापसी का हिस्सा होती, लेकिन मैं जहां हूं, वहां खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि स्मृति जी का नया शो सुपरहिट होगा, क्योंकि यह बहुत शानदार शो है, जो दर्शकों को आज भी बहुत पसंद है। टीवी के सुनहरे युग की वापसी पर अनुपमा ने कहा, शायद यह संभव हो। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उस दौर में भावनाओं और दर्शकों से जुड़ाव की जो गहराई थी, वह बेमिसाल थी। मैं चाहती हूं कि वह दौर लौटे। एकता मैम के शो अब कम आते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह नया शो दर्शकों के दिलों को छू लेगा।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2' का प्रीमियर 29 जुलाई को स्टार प्लस पर होगा। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय तुलसी और मिहिर विरानी की अपनी लोकप्रिय भूमिकाओं में वापसी करेंगे।

इस नए अध्याय में हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान, शक्ति आनंद, कमलिका गुहा ठाकुर, शगुन शर्मा, रोहित सुचंती, अमन गांधी, अंकित भाटिया और तनीषा मेहता जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

क्या धर्मा प्रोडक्शंस और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बीच होगी हाई-प्रोफाइल साझेदारी?

पीपल मीडिया फैक्ट्री की आगामी मेगा फिल्म 'मिराई', जिसमें तेजा सज्जा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के विजुअली दमदार पोस्टर और दमकते टीजर ने दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता और रोमांच पैदा कर दिया है। 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही 'मिराई', साल की सबसे चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन चुकी है। अब इंडस्ट्री में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है - खबरें हैं कि करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शंस, पीपल मीडिया फैक्ट्री की 'मिराई' के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। बाहुबली, 2.0 और अपकमिंग देवारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ रणनीतिक भागीदारी के लिए मशहूर धर्मा प्रोडक्शंस अगर 'मिराई' से जुड़ती है, तो फिल्म की पहुंच और लोकप्रियता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है।

एक सूत्र ने इस बारे में जानकारी दी, अगर धर्मा इस फिल्म से जुड़ती है, तो 'मिराई' एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगी। इससे इसकी पहुंच और दृश्यता देशभर में और उससे भी आगे तक फैलेगी। करण जोहर की जनमानस की समझ और धर्मा की मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता के साथ, 'मिराई' एक सच्चे मायनों में अखिल भारतीय इवेंट फिल्म बन सकती है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तेजा सज्जा, जो हाल ही में 2024 की पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर 'हनुमान' में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं कार्तिक गट्टमनेनी, जो अपनी विजुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जाने जाते हैं।

निर्माता हैं टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद, जिनका नाम महत्वाकांक्षी सिनेमा के निर्माण के



लिए जाना जाता है। 'मिराई' एक ऐसा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है जिसमें मिथकीय कथानक, तीव्र एक्शन और

अत्याधुनिक वीएफएक्स का अद्भुत संगम होगा। फिल्म की कहानी एक निडर योद्धा की है जिसे नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। फिल्म में मनोज मंचु और ऋतिका नायक भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिनके दमदार अभिनय से कहानी को गहराई और तीव्रता मिलती है। फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं गौरा हरि, जिनका बैकग्राउंड स्कोर कहानी की भावनात्मकता और भव्यता को और अधिक ऊँचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। पीपल मीडिया फैक्ट्री ने 2025 की धमाकेदार शुरुआत की है सनी देओल स्टारर जाट की सफलता के साथ। 'मिराई' के अलावा, उनके पास प्रभास की 'हॉरर-कॉमेडी' द राजा साब समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो यह साबित करते हैं कि वे साल भर बॉक्स ऑफिस की रेस में आगे रहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

रश्मिका मंदाना ने लॉन्च किया अपना फ्रेगरेंस ब्रांड



अ भिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने फ्रेगरेंस ब्रांड के लॉन्च की घोषणा की है। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि परफ्यूम उनके लिए एक ऐसी चीज है, जो अक्सर उन्हें उन खास पलों में वापस ले जाता है, जिन्हें वह भूल जाती हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का परफ्यूम ब्रांड 'डियर डायरी' मेरे निजी जीवन के अनुभवों और विचारों से प्रेरित है। अभिनेत्री ने बताया, मेरे लिए, खुशबू का मतलब यादें हैं। मुझे बहुत सी बातें याद नहीं रहतीं, या शायद कुछ चुनिंदा बातें ही याद रहती हैं, लेकिन परफ्यूम उन खास पलों को फिर से ताजा कर देता है जिन्हें मैं शायद भूल जाती हूं।

इसी तरह से मैं उन लोगों, जगहों और अनुभवों को याद रखती हूं, जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी बन पाई हूं।

उन्होंने आगे कहा कि 'डियर डायरी' के जरिए वह सभी को अपनी कहानियों में साथ ले जाने का एक तरीका देना चाहती हैं।

रश्मिका ने बताया, उनके परफ्यूम को लॉन्च करने का मकसद बस खुद से जुड़ना, सुकून महसूस करना, एक अच्छा अहसास पाना और बिना किसी झिझक के अपनी पहचान बताना है। रश्मिका ने अपने नए फ्रेगरेंस ब्रांड के बारे में बात करते हुए इंस्टाग्राम पर

एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, यह वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, न ही परफ्यूम है, बल्कि मेरा एक हिस्सा है। खुशबू हमेशा से मेरी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है... और आज मैं आपके साथ इसको साझा कर रही हूं। उन्होंने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे यह ब्रांड लॉन्च करने का मौका मिला और मैं इसको लेकर काफी उत्साहित भी हूं। मुझे उम्मीद है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सभी का साथ मिलेगा। इस घोषणा से पहले भी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा की थी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार इसे रिकॉर्ड कर रही हूं। जैसा कि आप अब तक जानते ही होंगे, मैं अपने दिल के बहुत करीब किसी चीज पर काम कर रही हूं। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि मैंने आपके लिए मेरा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा भी है। रश्मिका ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इसे महसूस करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा, यह कल लॉन्च हो रहा है, और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं।



शिक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में सात नए विभागों को अनुमति दी

बेंगलूर/शुभ लाभ ब्यूरो।

शिक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में सात नए विभागों/कार्यक्रमों की स्थापना को अनुमति दे दी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बट्टू सत्यनारायण ने गुरुवार को कडगांची स्थित विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम को नया रूप दिया है और छात्रों के रोजगारपरक कौशल में सुधार के लिए नवीन और कौशल-आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रो. सत्यनारायण ने कहा कि सीयूके परिसर में उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में मानवशक्ति को प्रशिक्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने इस केंद्र के अंतर्गत सीयूके की गतिविधियों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया



है। इस केंद्र की स्थापना 2 करोड़ से अधिक की लागत से की जा रही है, जिसमें केंद्र की औद्योगिक शाखा, कीसाइट टेक्नोलॉजीज के साथ 50 प्रतिशत की भागीदारी है।

कुलपति ने कहा कि सीयूके अनुसंधान, विकास और शैक्षिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय को इस शैक्षणिक वर्ष में 16 करोड़ से

अधिक का अनुसंधान अनुदान प्राप्त हुआ है, इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान हेतु सा-झेदारी (पीएआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत 11.5 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, सीयूके के रसायन विज्ञान विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसरचना सुधार निधि (एफआईएसटी) कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान विकास के लिए 1.67 करोड़ का समर्पित अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं विकास को सुदृढ़ करना है। विश्वविद्यालय को प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्य के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ का अनुदान और

सामाजिक कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक आदर्श आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए 1.21 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय में एक मजबूत अनुसंधान आधार बनाने के लिए 60 करोड़ के निवेश से एक समर्पित परिष्कृत उपकरण केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान उपकरण रखे गए हैं। उन्होंने दो-हराया कि शैक्षणिक, अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों के साथ-साथ, सीयूके बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल ही में, उच्च शिक्षा मंत्रालय ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और जीवन विज्ञान विभागों के लिए दो शैक्षणिक ब्लॉक, लड़कियों और लड़कों के लिए 500-500 बिस्तरों की क्षमता वाले दो छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 201.86 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया है।

गया (एजेंसियां)।

लंबे अंतराल के बाद गया जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक सितंबर से एयर इंडिया गया जी से दिल्ली के लिए उड़ानों की घोषणा की गई है। साथ ही एयर इंडिया ने टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि इकनोमिक के लिए 7122 और बिजनेस क्लास की कीमत 25 हजार रुपये रखी गई है।

पांच वर्षों के बाद गया जी एयरपोर्ट से एयर इंडिया की शुरुआत केवल लोकल यात्रियों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। खासकर वैसे लोगों के लिए जो विदेश से गया जी और बोधगया की यात्रा के लिए दिल्ली होते हुए हिन्दुस्तान आते हैं। उनके लिए इंडिगो के साथ अब एक और विकल्प एयर इंडिया भी होगी। यात्रियों को उड़ान के समय और किराए पर भी राहत मिलने की संभावना है।

देशी और विदेशी पर्यटकों को एयर इंडिया की सेवा शुरू करना काफी फायदेमंद होगा। वहीं, स्थानीय व्यवसायियों, छात्रों और



विदेशी पर्यटकों को दिल्ली की यात्रा के लिए दूसरा विकल्प उपलब्ध होंगे। मालूम हो की देश में कोरोनाख महामारी के क्रम में 2021 में गया एयरपोर्ट से एयर इंडिया की उड़ान अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया था। एयर इंडिया की उड़ान बंद कर देने के बाद सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। स्थानीय यात्रियों और व्यवसायियों की लगातार मांग कर रहे थे कि गया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए फिर से एयर इंडिया की भी उड़ान शुरू की जाए।

इधर, एयर इंडिया ने इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए दूर ऑपरेटर से संपर्क कर शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही टिकट की बुकिंग की शुरुआत कर दी है। एयर इंडिया के फ्लाइटों की सेवा शुरू होने के बाद गया हवाई

अड्डा की उपयोगिता और यात्री की ट्रैफिक दोनों में बढ़ोतरी होगी। एयर इंडिया की दिल्ली की उड़ान शुरू किए जाने की घोषणा के बाद लोगों में काफी खुश है।

एयर इंडिया फ्लाइट गया जी से दिल्ली की उड़ाने शुरू किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने अन्य स्थानों के लिए भी उड़ान शुरू किए जाने की मांग शुरू हो गयी है। इस संबंध में दूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप कुमारने बताया कि एयर इंडिया की टिकट बुकिंग की इंकारी आना शुरू हो गया है। इकोनोमिक क्लास का किराया 7122 और बिजनेस क्लास का किराया 25 हजार रुपये तक है। उन्होंने गया से दिल्ली के अलावा चेन्नई, मुंबई और बेंगलूर के लिए सीधी उड़ने शुरू होने से घरेलू और विदेशी पर्यटकों का बढ़ावा मिलेगा।

लोकायुक्त ने अधिकारी और सहायक को रिश्तत मांगते रंगे हाथों पकड़ा



उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो।

रिश्ततखोरी के एक मामले में, उडुपी जिला सहकारी समिति के लेखा परीक्षा विभाग की उप निदेशक रेणुका और प्रथम श्रेणी सहायक जयराम को लोकायुक्त पुलिस ने सौहार्द सहकारी समिति के चुनाव कराने के लिए रिश्तत मांगते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने सौहार्द सहकारी

समिति के प्रशासनिक बोर्ड के चुनाव कराने के लिए कथित तौर पर 10,000 रुपये - 5,000 रुपये - की रिश्तत मांगी थी। शांतिनिकेतन सौहार्द सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजेंद्र ने उडुपी लोकायुक्त पुलिस में रिश्तत की मांग के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई

छापेमारी के दौरान रेणुका को उडुपी स्थित उनके कार्यालय में रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई मंगलूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कुमारचंद्र के मार्गदर्शन में की गई। डीएसपी मंजूनाथ शंकरहल्ली, निरीक्षक राजेंद्र नायक और अन्य अधिकारी कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम का हिस्सा थे।

पटना (एजेंसियां)।

फुलवरिया जलाशय परियोजना (रजौली) से जुड़े विस्थापितों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में नवादा व्यवहार न्यायालय ने बड़ा और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। सब-जज प्रथम आशीष रंजन की अदालत ने मुआवजा भुगतान में देरी और अदालती आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस (परिसदन भवन) को कुर्क करने का आदेश दिया है।

जलाशय परियोजना के चलते विस्थापित हुए दर्जनों परिवारों की भूमि और मकान का मुआवजा वर्षों से लंबित है। इस संबंध में विभिन्न विस्थापितों ने न्यायालय



की शरण ली थी।

इन सभी मामलों में प्रतिवादी के रूप में बिहार सरकार, नवादा जिला समाहर्ता, फुलवरिया जलाशय परियोजना के कार्यपालक अभियंता एवं विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को शामिल किया गया है।

वाद संख्या 09/2021 में अदालत ने 2015 में ही गणेश पंडित को 6,58,687.21 की

बाल्मीकि प्रसाद ने वादी पक्ष के अधिवक्ता रंजीत कुमार पटेल के साथ नवादा समाहरणालय और सर्किट हाउस की दीवारों पर ढोल बजाकर कुर्की का इशतेहार चस्पा किया।

वादी पक्ष के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि वाद संख्या 03/2022 - शांति देवी व अन्य बनाम बिहार सरकार में भी न्यायालय ने समाहरणालय और परिसदन भवन को कुर्क करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ।

न्यायालय ने कई बार संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों की

लगातार अनदेखी और लापरवाह रवैया के चलते अदालत को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। यह मामला प्रशासनिक उदासीनता का ज्वलंत उदाहरण बन गया है, जहां वर्षों से प्रभावित परिवार न्याय के लिए भटक रहे हैं और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं।

विस्थापित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि मुआवजा भुगतान में देरी और अदालती आदेशों की अनदेखी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रही है। अदालत के सख्त रुख के बाद अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है।

डीएम-एसपी ने की सख्त कार्रवाई : आईसीडीएस डीपीओ को गिरफ्तार करने का दिया आदेश

सुपौल (एजेंसियां)।

सुपौल के आईसीडीएस कार्यालय में रिश्तत लेने के आरोप में गुरुवार को सदर थाने की पुलिस ने डीपीओ शोभा सिन्हा और डाटा एंट्री ऑपरेटर चंदन को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई डीएम सावन कुमार और एसपी सरथ आरएस के संयुक्त निर्देश में की गई। डीपीओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर को सदर थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है।

दरअसल नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षक से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर आईसीडीएस डीपीओ द्वारा 25 हजार रुपए की मांग की गई थी। रिश्तत नहीं देने पर बहाली रद्द



करने की धमकी दी गई थी। इसकी सूचना बुधवार से ही डीएम के पास थी। गुरुवार को जैसे ही एलएस ने आईसीडीएस कार्यालय पहुंचकर पैसे ऑपरेटर को दिए, डीएम अपने कार्यालय कक्ष से सीधा निकलकर आईसीडीएस कार्यालय पहुंचे। जांच के दौरान ऑपरेटर चंदन के पास से नकद रुपए बरामद हुए। पृच्छाछ में चंदन

ने स्वीकार किया कि यह राशि रिश्तत की है। उसने बताया कि डीपीओ के कहने पर उसने यह रुपए लिए हैं। इसके बाद डीपीओ के चैंबर में छापेमारी की गई। वहां से भी नकद रुपए मिले। छापेमारी के दौरान दोनों जगहों से कुल 1.80 लाख रुपए जब्त किए गए। डीएम सावन कुमार ने बताया कि मौके से बरामद राशि और अन्य साक्ष्य रिश्ततखोरी की पुष्टि करते हैं। यह गंभीर अनियमितता है। इसी आधार पर दोनों के खिलाफ

कार्रवाई की गई। इधर, इस छापेमारी से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है।

बुधवार को एक एलएस ने डीएम को इसकी शिकायत की। डीएम ने गुरुवार तक मामले को गोपनीय रखा। वही गुरुवार को आईसीडीएस कार्यालय के पल-पल की खबर डीएम गोपनीय रूप से रख रहे थे। जैसे ही एलएस ने ऑपरेटर को पैसे दिए, डीएम सीधा पहुंचे और ऑपरेटर की जेब से नगर राशि बरामद की। बाद में सीसीटीवी को खंगालने पर एलएस से ऑपरेटर द्वारा राशि लेने की पुष्टि भी हुई। जिसके बाद डीपीओ के केबिन से भी छापेमारी कर पैसे बरामद किए गए। मौके से

कुल 1.80 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी एलएस के बयान दर्ज किए। वही मामले की जांच जारी है।

जिले में जनवरी माह में 13 महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई थी। मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी को टाउन हॉल में सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा था। छह महीने बीतने के बाद भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ था। इसी कारण किसी को वेतन नहीं मिला था। हाल ही में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान डीपीओ द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर सभी एलएस से 25 हजार रुपए की मांग की गई थी।

सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

वैशाली (एजेंसियां)। वैशाली में सारण डीआईयू एवं जलालपुर थाने की पुलिस ने दो शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के नखाश चौक स्थित सीढ़ी घाट रोड वार्ड नंबर 13 निवासी शिवनाथ राम के घर पर की गई है। उनके पास से पुलिस ने 800 ग्राम सोना, 900 ग्राम चांदी और 53 लाख 30 हजार नगद बरामद किया है।

इस मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दोनों ठग सारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में घूम घूम कर भोले भाले लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कैश एवं आभूषण लेकर फरार हो जाते थे। भारी मात्रा में कैश एवं आभूषण मिलने के कारण सारण पुलिस को स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा से कैश मशीन एवं स्थानीय सोना दुकानदार का सहायता लेना पड़ा तब जाकर आभूषण की वजन एवं कैश की गिनती पूरी हुई। ठग की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नकाश चौक स्थित सीढ़ी घाट रोड वार्ड नंबर 13 निवासी शिवनाथ राम के पुत्र राकेश कुमार एवं मुकेश कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सारण जिले

की पुलिस को पिछले कई वर्षों से यह शिकायत मिल रही थी कि कोई ऐसा गिरोह है, जो सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है। इस तरह की ठगी करने वाला गिरोह ग्रामीण एवं शहरी के इलाकों में घर-घर घूम-घूमकर कर करता है। इसके बाद सारण जिले के एसपी के द्वारा ठगी गिरोह को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम के द्वारा जितने भी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसके आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर ठग गिरोह के सदस्य को पहचान की गई।

इसी दौरान जलालपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक महिला से फोटो खींचने के बहाने से आभूषण उतरवा लिया। जैसे ही महिला पानी लाने के लिए गई, शातिर ठग प्लांटिंग के अनुसार मिनट भर में फरार हो गए। इसके बाद महिला ने घटना की सूचना आसपास के लोगों को दी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास की लोगों ने घेराबंदी कर भाग रहे दो ठग को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

22 साल बाद दो भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा, आरोपी पिता की ट्रायल में हो चुकी है मौत

औरंगाबाद (एजेंसियां)।

22 साल पहले मामूली विवाद में भाई ने सगे भाई की अपने दो बेटों के साथ इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि इलाज के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक के बेटे ने प्राथमिकी दर्ज कराई और मामला 22 साल तक कोर्ट में चला। मामले में सगे

भाई की हत्या करने वाले को अदालत इस वजह से सजा नहीं सुना सकी क्योंकि हत्यारे भाई के साथ उपर वाले ने इंसाफ किया और उसकी मामले के ट्रायल के दौरान मौत हो गई। वही मामले में बिहार की एक अदालत ने चाचा की हत्या करने वाले दोनों सगे भतीजों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना के करमडीह गांव में सार्वजनिक कुआं तक आने-जाने के लिए गैर मजरूआ जमीन से रास्ता बनाने को लेकर के लिए गांव के ही महंग राम और उनके पुत्र सूचक और उनके पुत्र संजय राम का सहंग राम से विवाद हुआ था। इसी विवाद में

सहंग राम के दो लड़कों कृष्णा राम और कृत राम ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की।

पिटाई से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान महंग राम की अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले को लेकर करमडीह निवासी संजय राम ने 26 जून 2003 को

मदनपुर थाना में प्राथमिकी संख्या- 67/2003 दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा था कि उनके पिता महंग राम गांव के सार्वजनिक कुएं तक गैर मजरूआ जमीन से होकर जाने के लिए सुगम रास्ता बना रहे थे। इस दौरान उसके चाचा सहंग राम ने रोका और अपने दोनों बेटों संग मिलकर पीटने

लगे। बचाव करने पर तीनों ने मिलकर उसे भी पीटा और पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पिता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई जबकि वह जीवित बच गए। इसी मामले की गुरुवार को हुई अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने दोनों भतीजों को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि मामले

के ट्रायल के दौरान ही सूचक के सगे चाचा की मौत हो जाने के कारण कोर्ट द्वारा तकनीकी कारणों से सजा नहीं सुनाई जा सकी। इसी मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला जज राजकुमार की अदालत ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई की और फैसला सुनाया।